साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-29 अंक- 37 11 - 17 सितंबर 2022 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

कमज़ोर रुपए से बढ़ती मुश्किलें
पृष्ठ - 6

बंजर होती ज़मीन के ख़तरे
पृष्ठ - 7

राजनीत में अपराध के दबदबे के इस दौर में चुनावी सुधार

कितना सफल हो सकेगा चुनाव आयोग?

आज हमारी राजनीति में बिना किसी दल विशेष के जिस प्रकार अपराध का बोलबाला हो रहा है, उसने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या चुनाव आयोग केवल प्रस्ताव द्वारा ही चुनाव सुधारों के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा।

हम जिस समाज में जीवन गुज़ार रहे हैं वह ख्वाहिशात और उम्मीदों का समाज कहलाता है। हमारे समाज में हर सुबह का सूरज अपने निकलने के साथ न मालूम कितने उम्मीदें और ख़्वाहिशात को उभारता है और जब ये सूरज शाम को डूबता है तो पता चलता है कि हमारी उम्मीद सफलता तक पहुंचते-2 मायूसी में बदल चुकी है। देश में चुनावी सुधार का विषय भी कुछ ऐसा ही है। कभी चुनाव आयोग, या कोई मंत्री या कोई बड़ा राजनैतिक पार्टी का चुनावी सुधार पर कोई बयान देता है, तो देश का वोटर बड़ी उम्मीद की नज़रों से उसका स्वागत करता है, मगर जैसे ही इस बयान की स्याही सूखती है, मायूसी का भूत फिर सामने आ जाता है, जो पिछले 75 सालों से देश की जनता देख रही है। हमें नहीं मालूम हम यह बात कब समझ पाएंगे कि किसी भी देश के निष्पक्षता चुनावी निष्पक्ष प्रक्रिया में छुपी है। जो रुपए पैसे की ताक़त और सत्ता के प्रभाव से पाक हो। मशहूर कहावत है ''अगर समाज व्यक्ति बनाता है, तो व्यक्ति भी समाज से ही बनता है।'' इस कहावत का अर्थ यही है कि समाज में हर व्यक्ति की राय की अहमियत होती है और सरकार को उसकी अहमियत को समझना चाहिए, जहां तक चुनावी सुधार का प्रश्न है, चुनाव का सीधे तौर पर जनता पर प्रभाव पड़ता है इसलिए आवश्यकता है कि पहले यह देखा जाए कि वह कौन से क्षेत्र है जिनको स्वयं चुनाव आयोग ने बहस का विषय बनाया, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें राजनैतिक दलों ने पेश किया और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर अभी तक बहस नहीं हो पाई है।

यहां प्रश्न यह भी है कि क्या हमारे क्या देश की जनता अपने मतदाताधिकार का प्रयोग अपने परिपक्वता और समझ और ठीक जानकारी के साथ प्रयोग करते हैं, क्या दल-बदल क़ानून अपनी अहमियत को खो चुका है। क्या चुनाव के बाद सत्ता प्राप्ति के लिए जोड़-तोड़ हमारे लोकतंत्र के लिए ख़तरा है, और अभी तक हमारे वोटर 'नोटा' की अहमियत समझने के लिए दिलचस्पी नहीं ले न ही उसका प्रयोग करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। असल बात यह है कि हमारे राजनैतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए भारतीय संविधान की इस बात को ही भुला दिया है जो किसी कमज़ोर, लाचार और बेरोज़गार के लिए रास्ता दिखा सकती है। आज देश की सियासत में धर्म और ज़ातपात की राजनीति का बोलबाला, जिसने मजबूर और लाचार लोगों को यहां तक पहुंचा दिया है जहां उनकी सांविधानिक अहमियत के बावजूद कोई पूछ नहीं है। आज हमारे राजनैतिक लोगों को धर्म और ज़ात-पात की अफीम पिलाकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, जिसने चुनावी सुधार पर गहराई से सोचने की आवश्यकता और अहमियत को बढ़ा दिया है। हम देशप्रेमी हैं, हिन्दोस्तान हम सब का देश है, यही हमारी आन-बान-शान है, ये तिरंगा हमारी आपसी एकता की पहचान है। राजनीति में बड़ी लकीर को छोटा करने और खींच-तान की जिस राजनीति का हम तस्सवुर करते हैं, अगर उसका असली चेहरा हमारे सामने आए जाए तो हम शर्मिन्दा हुए बिना नहीं रह पाएंगे! क्या

बाक़ी पेज 11 पर

मदरसों की हर हाल में सुरक्षा की जाएगी

मौलाना सैयद महमूद मदनी

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के तत्वाधान में मदरसों के सहयोग के लिए कमेटी गठित

स्वतंत्र मदरसों विशेषकर उत्तर प्रदेश के मदरसों के समक्ष मौजूद चुनौतियों के संदर्भ में दिनांक 09/06/2022 को नई दिल्ली स्थिति जमीयत के केन्द्रीय मुख्यालय में 'मदरसों की सुरक्षा' के विषय पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें दारुल उलूम देवबंद, नदवतुल उलेमा लखनऊ, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर समेत उत्तर प्रदेश के दो सौ से अधिक मदरसों के संचालक एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 12 प्रश्नों पर आधारित सर्वेक्षण पर प्रकाश डाला गया और उसके कारणों और संदर्भ को पावर प्वाईंट प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से बताया गया।

इस अवसर पर मौलाना महमूद मदनी अध्यक्ष जमीयत उलेमा ने बताया कि जमीयत एक कमेटी बनाएगी और वह कमेटी यूपी सरकार से मुलाक़ात करेगी। जिसमें जमीयत सर्वे का विरोध नहीं करेगा। महमूद मदनी ने कहा कि 'हम सर्वे से जुड़े अधिकारियों को एक आवेदन भेजकर उनसे मिलने का वक्त मांगेंगे। कोई भी काम गलत तरीक़े से नहीं होना चाहिए, भले ही वह अच्छा काम ही क्यों न हो, कुछ सुधार करने के लिए हमेशा जगह होती है, जिस तरह से मदरसों की गलत तस्वीर पेश की जा रही है, वह सही नहीं है, उन्होंने कहा कि ''आपने देखा कि असम में क्या हुआ, अगर यह तरीक़ा अपनाया जाता है तो यह अवैध है।''

इस अवसर पर अमीर-उल-हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे मदरसे साम्प्रदायिक लोगों की आंखों में कांटे हैं, इसलिए उनकी मंशा को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यवस्था को सुधारने की बात अपनी जगह है लेकिन हमें अपने मदरसों के अस्तित्व को बचाने के लिए तत्पर रहना होगा। हमने हमेशा कोशिश की है कि शांति के साथ हमारे धार्मिक संस्थानों को चलने दिया जाए लेकिन साम्प्रदायिक शक्तियां हमारे अस्तित्व को समाप्त करना चाहती हैं, जिसे हम कभी नहीं होने देंगे। उन्हांने कहा कि इस्लामी मदरसों का अस्तित्व देश के विरोध के लिए नहीं बल्कि देश के निर्माण के लिए है इसका डेढ़ सौ वर्षीय इतिहास गवाह है कि यहां से हमेशा देश के निर्माण का काम हुआ है।

दारुल उलूम देवबंद के कुलपति मुफ़्ती अबुल क़ासिम नोमानी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 'मदरसों की आंतरिक व्यवस्था को ठीक करने पर हमें विचार करना चाहिए। विशेषकर छात्रावासों आदि से संबंधित जो व्यवस्था है, उसका पालन करने की हर संभव कोशिश की जाए लेकिन अत्याचार करने वालों के इरादों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने जमीयत उलेमा-ए-हिन्द को बधाई दी कि इसने कम समय में पर्याप्त सूचनाप्रद सभा आयोजित की। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना मोहम्मद सुफियान क़ासमी ने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद का सौ वर्षीय इतिहास गवाह है कि इसने हमेशा देश और समाज का मार्ग दर्शन किया। हम आशा करते हैं कि इस कठिन समय में वह मदरसों के लोगों का मार्ग दर्शन करेगी। इस संबंध में उन्होंने एक हेल्पलाइन स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा।

दारुल उलूम नदवतुल उलमा के नाज़िम मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी का प्रतिनिधित्व करते हुए मौलाना अतीक अहमद बस्तवी ने कहा है कि सर्वे में उल्लिखित प्रश्नावली का उद्देश्य सुधार नहीं बल्कि कटुता है, इसलिए सांप्रदायिकता की इस नई सोच का उचित जवाब दिया जाए।

इस संबंध में उन्होंने सलाह दी कि सरकार के ज़िम्मेदारों से भी संपर्क किया जाए। उनके अलावा मुफ्ती मोहम्मद सालेह नायब नाज़िम जामिया मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, मौलाना सैयद हबीब अहमद बांदवी, मोहतमिम जामिया अरबिया हथोडा बांदा, मौलाना अब्दुर्रहीम नाज़िम आला, मदरसा अरबिया रियाज़ उल उलूम गुरैनी, मुज्तबा फारूक जमात-ए-इस्लामी हिंद, कमाल फारूकी सदस्य ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलाना मुश्ताक़ अतफर असम, मौलाना अशरफ मदरसा नूरूल उलूम प्रतापगढ़, प्रोफेसर मोहम्मद नोमान शाहजहांपुरी, मौलाना मोहम्मद यामीन मोबल्लिग, दारुल उलूम देवबंद, मौलाना असजद क़ासमी लखीमपुर, मौलाना शरीफ़ कासमी देवबंद, मौलाना अमीनुल हक़ अब्दुल्ला कानपुर आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए और सुझाव प्रस्तुत किए जिसके आलोक में तीन सूत्रीय सुझावों को स्वीकृति दी गई।

इस बैठक में मदरसों के विरुद्ध विभिन्न राज्यों में जारी कार्रवाई और उसके समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और सचिव जमीयत उलेमा-ए-हिंद मौलाना नियाज़ अहमद फारूक़ी ने एक महत्वपूर्ण प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक का संचालन संयुक्त रूप से जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन क़ासमी और जामा मस्जिद अमरोहा के सद्र-अल मुदर्रेसीन मुफ़्ती मोहम्मद अफ़्फ़ान मंसूरपुरी द्वारा किया गया।

बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी के ग़ैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। सर्वे के दौरान मदरसों में मौजूद बुनियादी ज़रूरतों की जांच की जाएगी।

इस फैसले की घोषणा यूपी सरकार में अल्पसंख्यक राज्य कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने पिछले दिनों की थी, जिसके ख़िलाफ़ जमीयत ने ये बैठक आयोजित की है।

सुलु वंशजों के साथ ज़मीनी विवाद में उलझा मलेशिया

फ्रांसीसी कोर्ट ने मलेशिया सरकार को आदेश दिया है कि वह सुलु सुल्तान के वंशजों को 15 अरब डॉलर का मुआवज़ा दे। इस मुद्दे ने मलेशिया की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। बरसों से शांत पड़े सुलु और 2013 के लहद दातू कांड ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। आख़िर यह मामला क्या है और इसका क्या असर होगा?

दरअसल, मलेशिया की गैस और तेल उत्पादक सरकारी संस्था पेट्रोनास को कहा गया है कि वह सुलु सुल्तान के वंशजों को उपनिवेश काल से ब्रिटिश मलेशिया और सुलु राजाओं के बीच 144 साल पहले हुए समझौते के तहत 15 अरब डॉलर की मुआवज़ा राशि दे। ब्रिटिश काल के समझौते को मलेशिया ने 2013 में एकतरफा निर्णय लेकर ख़ारिज कर दिया और सुलु पक्ष को मुआवज़ा मिलना भी बंद हो गया।

मलेशिया सरकार के इस निर्णय के विरोध में सुलु पक्ष ने 2017 में एक याचिका दायर की लेकिन मलेशिया में उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया और अब ऐसा लग रहा है कि बात बहुत बढ़ गई है। इस वर्ष की शुरुआत में फरवरी में फ्रांस की आब्रिटेशन कोर्ट ने सुलु सुल्तान के वंशजों के पक्ष में निर्णय दिया था। सुलु राजघराने के लोगों को फैसला तो मनचाला मिल गया लेकिन उस फैसले को अमली जामा पहनाना एक बड़ी चुनौती थी।

इस काम को मलेशिया और उसके आसपास के इलाक़े में करना बड़े विवाद को जन्म दे सकता था। शायद यही वजह है कि उन्होंने मुआवज़े की वसूली के लिए पेट्रोनास की लक्जमबर्ग स्थित 2 इकाइयों पर कब्ज़े की कोर्ट से अपील की और उन्हें इस मामले में कोर्ट की अनुमति भी मिल गई। हालांकि सरकारी सूत्रों की मानें तो मलेशिया सरकार ने इस मामले में अपनी संप्रभुता पर संभावित ख़तरे की दुहाई देते हुए 13 जुलाई 2022 को एक स्थगन आदेश पारित करा लिया।

मलेशिया में यह बात दूर कहीं लगी आग के धुएं सी पहुंची और चुनावी जंग में डूबने को बेचैन नेताओं को आपसी छींटाकशी का मौक़ा मिल गया। मलेशिया के प्रधानमंत्री इस्माईल साबरी का यह बयान कि मलेशिया सबाह प्रांत की एक इंच ज़मीन भी किसी को नहीं देगा और इसकी सुरक्षा और संप्रभुता अक्षुण्ण रखेगा, अपने आप में दिखाता है कि मलेशिया इस बात को लेकर कितना संजीदा है।

और क्यों न हो, आज सबाह मलेशिया का तेल और गैस निर्यात का प्रमुख स्रोत बन गया है लेकिन साबरी की कठोर वाणी से भी विपक्ष नहीं पिघला। भ्रष्टाचार के मामलों, खासतौर पर 1 एम.डी.बी. गबन मामलों में अपनी सत्ता गंवा चुके और कोर्ट के चक्कर काट रहे नजीब रज़ाक ने अवसर का फायदा उठाते हुए उनके बाद आई सरकारों और उनके मंत्रियों की लापरवाही पर सवालिया निशान लगाए और भूतपूर्व अटॉर्नी जनरल टॉमी थॉमस को इस बात का दोषी क़रार दे दिया। बात कुछ इस तरह तूल पकड़ चुकी है कि इस मुद्दे पर विपक्ष ने संसद में बहस कराए जाने की मुहिम भी चला दी। हालांकि सदन के अध्यक्ष ने नियमों और मामले के न्यायालय के विचाराधीन होने का हवाला देकर इसे किसी तरह फिलहाल के लिए टाल दिया है।

सबाह के कुछ लोगों और राजनीतिज्ञों ने यह आवाज़ भी उठानी शुरू कर दी है कि सबाह प्रदेश के अतीत, वर्तमान और मलेशिया के साथ उसके भविष्य पर खुली चर्चा हो।

मलेशिया भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद का शिकार रहा है। 1878 में अंग्रेज़ों ने विवादास्पद ज़मीन सुलु के सुल्तान से लीज पर ली थी, जो सबाह और आस पास के तमाम द्वीपसमूहों में फैली थी। यह समझौता सुलु सुलतान जमाल अल आलम, हांगकांग की गुस्तावुस बैरन वोन ओवरबेक और ब्रिटिश नार्थ बोर्निया कंपनी के बीच हुआ था, जिसके तहत कंपनियों ने सुलतान और उसके वारिसों को 5000 पेसो सालाना हमेशा के लिए देने की बात कही थी।

सुलु वंशजों का कहना है कि यह ज़मीन किराए पर ली गई थी, लेकिन मलेशियाई सरकार मानती है कि समझौता सबाह के ऊपर मालिकाना हक़ का था, किराए पर ज़मीन लेने का नहीं। उस समय तो मलेशिया आज़ाद ही नहीं था और समझौते पर हस्ताक्षर भी ब्रिटिश और हांगकांग स्थित कंपनियों के थे। 1936 में सुल्तान जमाल के बेऔलाद मरने के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने 9 नज़दीकी वारिसों को चुना और उन्हें मुआवज़े की रक़म देनी चालू कर दी।

1963 में मलाया को आज़ादी मिलने के बाद यह हिस्सा सुलु सल्तनत के पास जाने की बजाय आज़ाद मलाया का हिस्सा बन गया। सुलु वंश के वंशजों की मानें तो यह ग़लत था और अंग्रेज़ों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस विवाद में मलेशिया और सुलु सुल्तान के वंशजों के बीच ही विवाद नहीं रहा, एक समय इंडोनेशिया का भी इस क्षेत्र पर कब्ज़ा रहा था और ब्रुनेई का भी। हालांकि दोनों ही देश अब इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते।

2013 तक मलेशिया और सुलु सुल्तान के वंशजों के बीच भी शांति रही थी लेकिन 2013 में एक सुलु वंशज की भेजी मिलिशिया से हिंसक संघर्ष के बाद मलेशिया सरकार ने सुलु वंशजों को दिए जाने वाले 5300 मलेशियाई रिंगिट के सालाना भत्ते को बंद कर दिया।

बहरहाल अब मामले में नए पेंच निकल पड़े हैं। सुलु वंशज चाहते हैं कि जल्द से जल्द मामले का निस्तारण हो और इसके लिए न्यूयार्क कन्वेंशन का हवाला देते हुए उन्होंने किसी भी तीसरे हस्ताक्षरकर्ता देश में जाकर इस फैसले के अमल का मंसूबा बांधा है। जो भी हो, इस मुद्दे ने सबाह के मलेशिया के साथ संबंधों,मलेशिया की घरेलू राजनीति और विदेशि नीति पर असर डालना चालू कर दिया। सबाह की स्वायत्तता का मसला भी इस बात से उठेगा, यह भी तय है। मलेशिया पर इस मुद्दे के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ❑❑

छह वर्ष में ही दिल्ली की हवा में ज़हर घोर रही डीजल कारें

राजधानी में प्रदूषण के लिए सरकार ने डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष की आयु तय की है। हालांकि, अपनी उम्र सीमा के पूरा होने से पहले सिर्फ छह सालों में ही कारें वातावरण में ज़हर घोलना शुरू कर देती है। यह बात हाल ही में दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) द्वारा किए गए एक अध्ययन में सामने आई है। यह अध्ययन स्प्रींजर के पर्यावरण विज्ञान और प्रदूषण अनुसंधान (ईएसपीआर) जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

डीटीयू के पर्यावरणीय अभियांत्रिकी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि अध्ययन के लिए गाड़ियों की उम्र, माइलेज व रख रखाव को आधार बनाया गया था। साथ ही इसमें देश में कारे बेच रही पांच प्रमुख कंपनियों की डीजल गाड़ियों को शामिल किया गया। इसमें वे सभी कारें थीं, जो दिल्ली की अलग-अलग अथॉरिटी में पंजीकृत थीं। पता चला कि जिन गाड़ियों की आयु छह वर्ष से अधिक हो गई थी वे कारें अधिक प्रदूषण कर रही थी। गाड़ियों की माइलेज को लेकर प्रमुख ज़िम्मेदार पाई गई। जिन गाड़ियों की अच्छी देखभाल की गई थी, वे कारें कम प्रदूषण कर रही थी। अध्ययन में शामिल अभिनव पांडेय ने अध्ययन में देखा गया कि भारत स्टेज-4 की गाड़ियां, जिनका रख रखाव अधिक रखा गया था, वे बीएस-3 की खराब श्रेणियां में रखी गई गाड़ियों से कम वातावरण को प्रदूषित कर रही थी। बीएस-4 श्रेणी के वाहन साढ़े सात साल पूरा होने के बाद मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे, जबकि बीएस-3 श्रेणी में नौ साल बाद वाहनों मानकों को पूरा करने में विफल हो रहे थे। इसी प्रकार बीएस-4 श्रेणी में वाहन 95 हजार किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मानकों पर खरे नहीं उतरे। जबकि बीएस-3 श्रेणी में 1 लाख 25 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद वाहन मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे।

एम्स में बढ़ेंगी किडनी व अन्य रोगों के इलाज की सुविधाएं

एम्स में नवनिर्मित मातृ एवं शिशु ब्लाक में आइपीडी (इन पेशेंट डिपार्टमेंट) शुरू होने पर बच्चों व महिलाओं को इलाज की अच्छी सुविधा मिलेगी। पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक सर्जरी व गायनी विभाग को मातृ व शिशु ब्लाक में स्थानांतरित किए जाने से एम्स के मुख्य अस्पताल में करीब 200 बेड ख़ाली होंगे। इस वजह से किडनी, लिवर, रक्त विकार, हड्डियों की बीमारियों से पीड़ित मरीज़ों व इमरजेंसी में इलाज के लिए पहुंचने वाले गंभीर मरीज़ों के इलाज की सुविधा भी बढ़ेगी।

मातृ व शिशु ब्लाक में ओपीडी सेवा पहले से शुरू हो चुकी है। जल्द इसमें आइपीडी सुविधा शुरू करने की तैयारी है। यही वजह है कि एम्स प्रशासन ने हाल ही में आदेश जारी कर तय कर दिया है कि मुख्य अस्पताल के ख़ाली हुए वार्ड में हेमेटोलॉजी, गेस्ट्रोलॉजी, नेफ्रोलाजी, मेडिसिन, इमरजेंसी, यूरोलाजी व आर्थोपेडिक्स विभाग के मरीज़ों के इलाज के लिए अतिरिक्त बेड आवंटित किए जाएंगे। मौजूदा समय में एम्स के मुख्य अस्पताल में पीडियाट्रिक विभाग में बच्चों के इलाज के लिए करीब 100 बेड है। इसके अलावा पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए करीब 40 बेड व गायनी विभाग के लिए करीब 60 बैड निर्धारित हैं। ये तीनों विभाग 400 बेड के नवनिर्मित मातृ व शिशु ब्लॉक में स्थानांतरित किए जाएंगे।

ओपीडी में पिछले 15 सालों में किडनी के मरीज़ों का दबाव करीब पांच गुना बढ़ा है, जबकि 33 सालों में एम्स में किडनी के इलाज की सुविधा नहीं बढ़ी है। किडनी के इलाज के लिए 24 बेड ही उपलब्ध हैं। नेफ्रोलॉजी विभाग ने एम्स प्रशासन व केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से सुविधाएं बढ़ाने की भी मांग की है। आपातकाल में भीड़ के कारण गंभीर मरीज़ों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। इसीलिए इमरजेंसी सेवा में सुधार के साथ-साथ सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं में भी विस्तार की ज़रूरत महसूस की जा रही है। गेस्ट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ईएनटी, आर्थोपेडिक्स वे इमरजेंसी के लिए अतिरिक्त बेड आबंटित होने से मरीज़ों को भी राहत मिलेगी।

महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित है राजधानी

दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित है। नेशनल क्राइम रिकार्डस ब्यूरो के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल राजधानी में हर दिन दो नाबालिग लड़कियों के साथ रेप की वारदात हुई। दिल्ली में 2021 में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध की 13,892 घटनाएं हुईं। 2020 की तुलना में ये घटनाएं 40 प्रतिशत ज़्यादा है। देश के सभी 19 बड़े शहरों में महिलाओं के ख़िलाफ़ जितनी भी अपराध की घटनाएं होती हैं, उनमें से 32 प्रतिशत घटनाएं सिर्फ दिल्ली में होती है। दिल्ली के बाद मुंबई में 5543 और बेंगलुरु में 3127 अपराध महिलाओं के ख़िलाफ़ हुए। दिल्ली में महिलाओं की कीडनैपिंग से जुड़ी 3948, पति की क्रूरता की 4674 और नाबालिग़ बच्चियों से रेप की 833 घटनाई हुईं। ये घटनाएं 20 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में सबसे ज़्यादा है। राजधानी में 2021 में दहेज के लिए हत्या की 136 घटनाएं भी हुईं। ये भी सभी शहरों में होने वाली ऐसी घटनाओं का 36 प्रतिशत है। पिछले साल 2022 मामलों में महिलाओं का रेप करने के उद्देश्य से उन पर हमला किया गया।

देश में पिछले वर्ष 19 महानगरों में से दिल्ली में अपहरण के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय राजधानी में 2020 में अपहरण के सबसे अधिक 5475 मामले सामने आए थे, जबकि पिछले वर्ष 4011 मामले सामने आए। एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी में हत्या के मामलों में मामूली कमी दर्ज की गई। दिल्ली में 2021 में 461 और 2019 में 500 मामले आए थे। आंकड़ों के अनुसार, 2021 में राजधानी में दर्ज किए गए हत्या के ज़्यादातर मामले विभिन्न विवादों का नतीजा थे, जिनमें संपत्ति और परिवार से जुड़े विवाद शामिल हैं। हत्या के 23 मामलों में प्रेम प्रसंग के कारण खून-ख़राबा हुआ और 12 हत्याएं अवैध संबंधों के कारण हुई। इनमें 87 हत्याओं के पीछे निजी दुश्मनी वजह थी जबकि 10 हत्याएं निजी फायदे के कारण की गई।

संपादकीय

शांति मिशन

गडकरी का भाजपा के संसदीय बोर्ड से स्थगन

क्या ये आरएसएस के लिए कोई संदेश है

राजनीति का खेल भी बड़ा अजीब है। राजनीति में कल क्या होगा कोई नहीं जानता। आज जिसनेता की राजनीति में वर्चस्व है, उसके अगले दिन पता चलता है कि वह राजनीति के अंधेरे कुएं में फंसा हुआ दिखाई प्रतीत होता है। 2014 में जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताते हुए उन्हें उंगली पकड़कर प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, परंतु प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकार गठन के दौरान न केवल उनकी उपेक्षा की गई, बल्कि उनके दिमाग़ को कमजोर करने और जताने का भी प्रयास किया गया। उनकी अयोग्यता पर मुहर लगाने के लिए बाक़ायदा राजनीतिक दांव-पेंच का इस्तेमाल कर उनको हाशिए पर लाने की प्लानिंग की गई। इन्हीं राजनीतिक दांव-पेंच का इस्तेमाल करते हुए वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिह्ना और जसवंत सिंह की उपेक्षा की गई और उन्हें मार्ग दर्शक मंडल बनाकर छोड़ दिया। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि 2014 में भाजपा को इस स्थान तक पहुंचाने में इन वरिष्ठ नेताओं की पूरी ज़िन्दगी की मेहनत को भी अनदेखा कर दिया गया उन्हें मार्ग दर्शक मंडल का तमगा देकर चुपचाप सब कुछ होते देखने को मजबूर कर दिया गया।

2014 में जब नरेन्द्र मोदी और अमित शाह ने भाजपा की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली और हर फैसले में उनके आगे किसी को कोई टिप्पणी या शंका करने की अनुमति नहीं है। अब एक बार फिर मोदी/शाह की जोड़ी ने ऐसा ही खेल खेला है और परिवहन मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के वफादार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस खेल का शिकार बनाया गया जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, इस खेल में योगी आदित्यनाथ को भी संलिप्त करते हुए इन तीनों को भाजपा संसदीय बोर्ड से निष्कासित कर दिया, जिससे गडकरी जो कि इस सरकार के सबसे कर्मठ और ईमानदार नेता के तौर पर उभरकर सामने आए हैं, उन्हें विशेष फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह कई बार पार्टी लाइन से हटकर अपने निष्पक्ष राय रखी। हाँ, शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ के लिए यह एक चोट ही कही जाएगी।

श्री योगी आदित्यनाथ जिन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर प्रचारित कराया गया और माना जाता था कि उन्हें विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित करने में आना कानी की गई उन्होंने न केवल अपने नाम की उम्मीदवारी घोषित करने में अपना दमखम दिखाकर न सिर्फ सफलता हासिल की, अपितु पूरे चुनावी प्रचार को अपने अंतर्गत ही संचालित किया, जिससे आलाकमान उनसे नाराज़ बताया जाता है और पूरा भाजपा-जेपी आलाकमान देखता रह गया। यह प्रकरण राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना था। निस्संदेह योगी जी ने आलाकमान को पार्टी की सत्ता में वापसी का आश्वासन दिया और अपने अथक प्रयास और संघर्ष से अपने वादे और दावे को पूरा करने में सफलता प्राप्त की। भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में और अब जब मोदी/शाह की जोड़ी ने योगी को पार्टी के एक्शन बोर्ड और संसदीय बोर्ड के पदों से हटा दिया तो रास्ता दिखा उन्होंने अपनी ताक़त का भी एहसास कराया है।

यही हाल शिवराज सिंह चौहान का भी है। सरकार और प्रशासन में अपने सालों के अनुभव के बावजूद, वह मोदी/शाह की जोड़ी के राजनीतिक खेल के शिकार हो गए। मोदी शाह ने उन्हें अपनी चालाकी की राजनीति के लिए कोई ईनाम नहीं दिया बल्कि उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों बुनियादी पदों से बर्खास्त कर बाहर का रास्ता दिखाया।

दरअसल भाजपा में हालिया बदलाव के द्वारा पार्टी ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि जिस तरह पूरे देश में भाजपा की सत्ता का सपना हमने अपने शक्ति और सूझबूझ संकल्प के साथ पूरा करने में लगे उसमें किसी और की राय मायने नहीं रखती सिवाय दो व्यक्तियों के। और पार्टी के सर्वेसर्वा श्री नरेन्द्र मोदी जी ही हैं। पार्टी ने फैसला करते हुए केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड और चुनाव कमेटी से निष्कासित करने के पिछे कुछ और लोगों को भी संदेश देने का अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा है जिनमें आर.एस.एस. भी है, क्योंकि गडकरी आर.एस.एस. के वफादारों में से हैं और संघ को उन पर पूरा भरोसा था। नितिन गडकरी के बारे में कहा जाता रहा है कि वह अपने काम में पूरे मन और लग्न से लगे रहे और पार्टी लाइन या ग़लत प्रचार की हां में हां नहीं भरी, बल्कि कई अवसरों पर उन्होंने पार्टी लाइन से अलग हटकर निष्पक्ष राय ज़ाहिर कि जैसे पिछले दिनों उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि ''जी चाहता है कि राजनीति छोड़ दूं, क्योंकि राजनीति में ग़रीब हित का कार्य नहीं रह गया।'' इससे भाजपा के आलाकमान में बेचैनी महसूस की गई। गडकरी यही नहीं रुके उन्होंने मौजूदा लोकतंत्र के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त की थी। शायद यही वही रही होगी कि भाजपा को आर.एस.एस. के नेतृत्व को यह संदेश देना पड़ा कि चाहे गडकरी संघ के कितने ही नज़दीकी क्यों न हो, पर पार्टी और सरकार में रहते हुए वह मोदी के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोल सकते, जबकि गड़करी अपनी बात खुलकर कहने वाले व्यक्ति हैं उन्होंने एक सभा में यह भी कहा कि उन्हें किसी मंत्री पद की लालसा नहीं रही।

देश में यह आम राय है कि पिछले 60 सालों में देश के लोकतंत्र एक व्यक्ति के इर्दगिर्द ही घूमती दिखी है, चाहे वह कितनी भी पार्टी की सरकार रही हो। हालांकि भाजपा में अटल बिहारी, वाजपेयी के समय में दूसरों को भी अपनी राय रखने की आज़ादी थी और सबकी बात सुनी जाती थी और पार्टी के अंदर भी उन्हें अपनी राय रखने का पूरा समय दिया जाता था, उनकी बात का अध्ययन किया जाता था, सबकी बात सुनने के बाद पार्टी जो फैसला लेती थी वह सबको स्वीकार्य होता था।

वर्तमान 8 सालों से पार्टी की परंपरा में पूरी तरह से परिवर्तन आ चुका है, अब पार्टी लाइन से हटकर या आलाकमान के विरुद्ध जाकर कोई बात कहता है तो आलकमान फौरन उसे उसका ठिकाना दिखा देता है। इसी डर से अनेक नेता चाहे वह केन्द्रीय कार्यकारिणी का हो या भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं को विकास कार्यों में कम और अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में ज़्यादा व्यस्त दिखाई पड़ते हैं, कुर्सी अपनी जब सलामत है तब आप मोदी/शाह के विरुद्ध कोई कार्य, या वक्तव्य नहीं देते।

इस राजनीति का दिलचस्प पहलू ये है कि जब स्वयं नितिन गडकरी पार्टी अध्यक्ष थे उस समय तकरीबन आधे सदस्य ब्राह्मण संपन्न वर्ग के थे, जो उच्च जाति के थे, दलित चेहरे के रूप में एकमात्र थावर सिंह गहलौत थे, यही नहीं 2007 में जब राजनाथ सिंह जब पार्टी अध्यक्ष बने तो उन्होंने उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति बोर्ड से दूर ही रखा था, फिलहाल इस बार पार्टी ने जो संसदीय बोर्ड का गठन किया उसने इतिहास में पहली बार एक सिंह नेता इक़बाल सिंह लाल को स्थान दिया है। इस से इतर आर.एस.एस. के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए भाजपा के केन्द्रीय संसदीय चुनाव बोर्ड से शाहनवाज़ हुसैन को एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर शामिल किया जाता रहा है, हालिया चुनावी गठन में से शाहनवाज़ को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।

बहरहाल, भाजपा अपने विभागों में किसे रखे किसे बाहर का रास्ता दिखाई ये उसका निजी मामला है, इन सब के बावजूद मोदी/शाह की जोड़ी पार्टी को जिस ओर ले जा रही है, उनके निर्णयों से सब हैरत में है और प्रत्येक मंत्री अपने को ख़तरे की लाइन पर महसूस करता रहता है। दरअसल इस पूरी कारकर्दगी से मोदी/शाह की जोड़ी आर.एस.एस. को भी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से संदेश देना चाहती है कि भाजपा में हमारी बात मान्य है, किसी का भी अतिरिक्त हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है।❑❑

तारीख़े इस्लाम

नबी पाक सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की जीवनी

4

हिजरत के दूसरे वर्ष मुसलमानों पर जेहाद फर्ज़ हुआ, रमज़ान के रोज़े, जक़ात सदक़ातुल फित्र और इदैन की नमाज़ें फर्ज़ हुईं। मस्जिद अकज़ा के बजाए बैतुल्लाह को जहत क़िब्ला क़रार दिया गया। फातमा अल जोहरा रज़ि॰ अल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत अली रजि॰ से हुआ। आप (सल्ल॰) की लख़्ते जिगर हज़रत रुकैया (रजि॰) का विसाल भी इसी वर्ष हुआ। हक़ व बातिल (सच व झूठ) का पहला गज़वा बदर भी इसी वर्ष हुआ।

हिजरत के तीसरे वर्ष आप (सल्ल॰) का हिजरत हफ्सा बिन्त उमर फारूक रज़ि. अन्हा से और उसके बाद हज़रत ज़ेनब बिन्त खज़ीमा रजि. अल्लाह अन्हा से निकाह हुआ, हज़रत हसन बिन अली रजि. की विदालत हुई, आपकी लख़्ते जिगर हज़रत उम्मे कल्सूम रजि. का हज़रत उस्मान रजि. अल्लाह अन्हा से निकाह हुआ। गुस्ताख रसूल काअब बिन अशरफ और अबू राफेअ को जहन्नुम रसीद किया गया। इसी साल गज़वा ओहद का वाक्या पेश आया।

हिजरत के चौथे वर्ष अबू नज़ीर का निर्वासन हुआ, हज़रत हुसैन रज़ि. अल्लाह अन्हा की विलादत हुई इसी वर्ष आप (सल्ल॰) का हज़रत उम्म सलमा रज़ि. से निकाह हुआ और शराब के हराम होने का आदेश भी इसी साल नाज़िल हुआ। हिजरत के पांचवें वर्ष शरई परदे का आदेश नाज़िल हुआ। ज़िना की सज़ा का हुक्म हुआ। सलातुल खौफ की मश्र वईयत हुई। तमीम की इजाज़त मिली, वाक्या इफ्क हुआ और अमां आएशा रज़ि॰ अल्लाह अन्हा की शान में सूरह अल नूर नाज़िल हुई, आप (सल्ल॰) की हिजरत जवेरिया बिन्त हारिस रजि. अल्लाह अन्हा से और हज़रत ज़ैनब बिन्त हजश (रजि.) से निकाह हुआ। गज़वा-ए-खंदक, गज़वाए बनी मिस्ताक और गज़वा-ए-बेयर मऊना पेश आया जिसमें 70 सहाबा कराम (रजि.) को धोखे से शहीद किया गया। (जारी)

येदियुरप्पा के तजुर्बे का लाभ भाजपा को सिर्फ कर्नाटक में नहीं, पूरे दक्षिण भारत में मिलेगा

अरुण सिंह

प्रश्नः- अगले वर्ष कर्नाटक में चुनाव हैं, भाजपा को वापसी की कितनी उम्मीद है और किस बूते.?

उत्तरः- भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में विकास के बहुत काम किए हैं। सबके विकास का काम किया है, किसी का तुष्टिकरण नहीं किया है। पार्टी में एकजुटता है जबकि कांग्रेस को देखें तो वहां सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार में काफी मतभेद हैं। सेंटर मं उनकी कोई काबिल लीडरशिप नहीं है।

प्रश्नः- यह चर्चा चल रही है कि भाजपा कर्नाटक के सीएम बोम्मबई को बदल सकती है.?

उत्तरः- यह सब कांग्रेस की फैलाई अफवाह है। वह अंत तक इस तरह का झूठ बोलते रहते हैं। मुख्यंत्री बदलने का कोई प्रश्न नहीं है। वह अनुभवी है, मैच्यौर हैं, कॉमन मैन का रिप्रेजेंट करते हैं। हम उन्हें क्या बदलेंगे।

प्रश्नः- आपका एक बयान आया था कि कर्नाटक में भाजपा के सबसे बड़े नेता येदियुरप्पा हैं। इसे बाद चर्चा होने लगी कि क्या बीजेपी बोम्मई के चहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी..?

उत्तरः- येदियुरप्पा चार बार के मुख्यमंत्री हैं। तीन बार नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। अब भाजपा संसदीय बोर्ड के नेता हैं। तो वह बडे नेता तो हैं ही। हम उनके मार्ग दर्शन में चुनाव लड़ेंगे और बोम्मई का नेतृत्व होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। येदियुरप्पा राज्य का दौरा करेंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे, उनकी पूरी गाइडेंस होगी। उनके अनुभव का पार्टी को पूरे दक्षिण भारत में लाभ मिलेगा।

प्रश्नः- कर्नाटक में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता की हत्या के बाद से कार्यकर्ता गुस्से में है। क्या कदम उठा रहे है?

उत्तरः- कोई गुस्से में नहीं है। युवा मोर्चा के दो लोगों ने इस्तीफा देने की बात कही थी, पर वह भी वापस ले लिया। भाजपा के ज़िला स्तर तक के भी किसी पदाधिकारी ने इस्तीफा नहीं दिया है। नाराज़गी की सारी बातें कांग्रेस फैलाती है। सरकार ने उस केस में तुरंत एक्शन लिया। दोषियों को पकड़ा भी।

प्रश्नः- भाजपा के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत अहम है क्योंकि उत्तर भारत में काफी जगह सेचुरेशन की स्थिति आ गई है। सीटों की संख्या कहां से बढ़ेगी?

येदियुरप्पा चार बार के मुख्यमंत्री हैं। तीन बार नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। अब भाजपा संसदीय बोर्ड के नेता हैं। तो वह बडे नेता तो हैं ही। हम उनके मार्ग दर्शन में चुनाव लड़ेंगे और बोम्मई का नेतृत्व होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। येदियुरप्पा राज्य का दौरा करेंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे, उनकी पूरी गाइडेंस होगी। उनके अनुभव का पार्टी को पूरे दक्षिण भारत में लाभ मिलेगा।

उत्तरः- 2019 के चुनाव से पहले भी लोग यही कहते थे कि 2014 में भाजपा ने जितनी सीटें जीती थीं अब तो उसे नीचे ही जाना है। लेकिन 2019 की तुलना में 2019 में भाजपा ने ज़्यादा सीटें जीती। वोट भी पांच करोड़ से ज़्यादा मिले। इसी तरह हम 2024 में और आगे बढ़ेंगे। यूपी में सीटें बढ़ेंगी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना सब जगह भाजपा की सीटें बढ़ेंगी।

प्रश्नः- बिहार में जेडीयू के अलग हो जाने से लोकसभा चुनाव में भाजपा को कितनी दिक्क़त होगी?

उत्तरः- कोई दिक्क़त नहीं होगी। लोकसभा चुनाव तो एकतरफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा। हम अपने गठबंधन का सदैव सम्मान करते हैं। अब ये अगर हमें छोड़कर जाएं तो हम क्या कर सकते हैं। हमने आज तक सभी को अपने किसी सहयोगी को छोड़ा नहीं है।

प्रश्नः- राजस्थान में भाजपा को क्या उम्मीद है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे?

उत्तरः- राजस्थान में जंगलराज है। एक हत्या होती है, उस पर हम आंदोलन करते हैं तो दूसरी हत्या हो जाती है। राजस्थान में क़ानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। जनता परेशान है और वह उस कांग्रेस सरकार से छुटकारा चाहती है। वहां करप्शन का भी अंबार है। राजस्थान में भाजपा ने विकास किया था, कांग्रेस सरकार ने दस वर्ष पीछे धकेल दिया। राजस्थान एक शांत प्रदेश था, उसे गहलौत सरकार ने अराजक प्रदेश बना दिया। उनका उद्देश्य बस अपनी कुर्सी बचाना है इसलिए वह विधायकों और करप्ट अधिकारियों के दबाव में काम करते हैं। हम चुनाव में क्राइम, करप्शन और कांग्रेस के कुशासन को मुद्दा बनाएंगे।

प्रश्नः- राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया कि 70 साल वालों को रिटायर हो जाना चाहिए। क्या वह वसुंधरा पर निशाना साध रहे थे?

उत्तरः- पार्टी में ऐसा कोई 70 वर्ष का क्राइटेरिया नहीं है। 70 वर्ष वाले भी चुनाव लड़ सकते हैं।

प्रश्नः- पर राजस्थान में भाजपा में इन-फाइटिंग भी बहुत है, कैसे निपटेंगे इससे?

उत्तरः- भाजपा में कोई इनफाइटिंग नहीं है। फाइटिंग देखनी है तो गहलौत और सचिन पायलट की देखिए। कभी कांग्रेस के विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो कभी मंत्री। कांग्रेस का ही विधायक कह रहा है कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस के विधायक ही अपने मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि माइनिंग में घोटाला हुआ है। ❑❑

रेवड़ियां बांटना ग़लत, लेकिन संसाधनों पर ग़रीबों का भी हक़

शिवराज सिंह चौहान

प्रश्नः- प्रधानमंत्री ने रेवड़ी संस्कृति के ख़िलाफ़ दोटूक बोला, आपका इस पर क्या रुख़ है?

उत्तरः- मैं प्रधानमंत्री से सहमत हूं, वोटों के लिए होड़ में पड़कर रेवड़ियां बांटना गलत है। मगर हमारे संसाधनों पर ग़रीब गुरबों का भी हक़ है और उनकी बुनियादी ज़रूरतों के लिए मदद और सहायता की ज़रूरत है।

प्रश्नः- आपने जो 32 लाख नौकरियों का वादा किया है, उसे कैसे पूरा करेंगे? यह तो बहुत मुश्किल मालूम पड़ता है?

उत्तरः- हम सरकारी भर्तियों का ऐलान करके, स्वरोज़गार योजनाओं को आपस में जोड़कर और यहां तक कि महिला स्वयं-सहायता समूहों के ज़रिए इसे अंजाम देंगे।

प्रश्नः-आपके पहले के कार्यकालों में कैलाश विजयवर्गीय संभावित चैलेंजर थे और अब गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने वह रोल ले ली है, आपका चौथा कार्यकाल चुनौतिविहीन नहीं रहने जा रहा?

उत्तरः-कैलाश विजयवर्गीय बचपन से ही करीबी दोस्त हैं और नरोत्तम जी भरोसेमंद साथी कार्यकर्ता हैं यहां तक कि कांग्रेस से आए मित्र भी अब हमारे साथ घुलमिल गए हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, वे दूध में शक्कर की तरह एकमेक हो गए हैं।

प्रश्नः- पिछले चुनाव का नारा था 'हमारा नेता शिवराज, माफ करो महाराज', इस कार्यकाल में आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ काम कर रहे हैं, राजनीति में यह समझ कैसे बनती है..?

उत्तरः- अगर आप में अहं नहीं है, अगर आप सबको साथ लेकर चल सकते हैं, तो प्यार से तो पहाड़ हिल सकते हैं, मैं यह केवल इंप्रेस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया या हमारे साथ आकर जुड़ने वाले दूसरे कांग्रेस नेताओं के साथ काम करते हुए कोई दिकक्क़त पेश नहीं आई।

प्रश्नः- फेरबदल के बाद आप भाजपा के संसदीय बोर्ड का हिस्सा क्यों नहीं हैं.?

उत्तरः- देखिए, ये पार्टी तय करती है कि कौन क्या काम करेगा। एक टीम है जो तय करती है कि कौन-सा काम किसे करना है। आप देश के बारे में सोचिए, पार्टी आपके बारे में सोचेगी। पार्टी ने मुझे इतना कुछ दिया है, कल अगर वह किसी कार्यक्रम में दरी बिछाने को कहेगी तो वह भी करूंगा।

प्रश्नः- कृषि में आप किन नए कार्यक्रमों की योजना बना रहे हैं.?

उत्तरः- प्रधानमंत्री कृषि आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम छोटे किसानों को वित्तीय सहायता दे रहे हैं। हम लाभदायक मूल्य देने के लिए फसले खरीदते है। पर भविष्य में फसलों में विविधता लाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए, अश्वगंधा सरीखे औषधीय महत्व वाले पोधे भी उगाए जा रहे हैं। हम एमएसएमई को भी सब्सिडी देते हैं और इसी तरह हम कृषि औज़ारों के लिए किसानों को भी ऐसी ही सहायता देंगे।

प्रश्नः- मामा से बुलडोजर मामा, यह कायापलट क्यों..?

उत्तरः- हम बिल्कुल शुरूआत से ही अच्छे लोगों के लिए नरम और अपराधियों के लिए सख़्त रहे हैं। जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया था, हाल ही में उन्हें बुलडोजर का निशाना बनाया गया यह जमीन फिर ग़रीबों को बांट दी जाएंगी इसमें ग़लत क्या है। ❑❑

सबसे बड़ी दिक्क़त यह है कि नौकरियां हैं ही नहीं : कमलनाथ

प्रश्नः- मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिए आपको दो वर्ष और पांच माह हो गए। सत्ता में नहीं होने की कमी खल रही है?

उत्तरः- बिल्कुल नहीं, मैं किसी भी हाल में सौदेबाज़ी को तैयार न था। मुझे विधायकों ने बताया कि उन्हें पैसे की पेशकश की जा रही थी। कुर्सी का कोई लालच न था, सरकार गई उसे जाना था, फिर मौक़ा आता है।

प्रश्नः- मध्य प्रदेश को दोबारा फतह करने की आपकी योजना क्या है.?

उत्तरः-हमारी लड़ाई केवल भाजपा से नहीं बल्कि उसके संगठन से भी है। इतना ही नहीं, हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि इस थोड़े से वक़्त में राजनीति किस कदर बदल गई है। पांच वर्ष पहले 25 प्रतिशत लोग सोशल मीडिया पर हुआ करते थे, अब 90 प्रतिशत हैं। भीड़ इकट्ठा करने से चुनाव जीतने में मदद नहीं मिलेगी।

प्रश्नः-आपकी पार्टी का बिखराव जारी है, आख़िर क्यों?

उत्तरः- जो जीतने वाले नहीं है, वे भाजपा में जा रहे हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता।

प्रश्नः- कांग्रेस ने मुरैना और ग्वालियर जीते। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए इसके क्या मायने हैं.?

उत्तरः- इलाके के लोगों ने बता दिया कि वे कहां खड़े हैं। ग्वालियर और मुरैना के नतीजों से बदलती राजनीति की झलक मिलती है, भाजपा को यह बदलाव समझना चाहिए।

प्रश्नः- शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के बारे में आपका क्या कहना है.?

उत्तरः- उन्हें न्यूज चैनलों के कार्यक्रमों में नहीं बल्कि मनोरंजन चैनलों के कार्यक्रमों में बुलाना चाहिए।

प्रश्नः- लेकिन वे क्या ग़लत कर रहे हैं.?

उत्तरः- उन्हें झूठ बोलना बंद करना चाहिए। 20 वर्ष में उन्होंने 20,000 घोषणाएं कीं। शिवराज सिंह चौहान ने भ्रष्टाचार को संस्थागत दर्जा दे दिया। यह मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं।

प्रश्नः- आप लंबे समय से राजनीति में हैं क्या 2023 के चुनाव को अपनी ज़िन्दगी की लड़ाई के तौर पर देखते हैं.?

उत्तरः- उपलब्धि और सिद्धि में फर्क है। मेरे लिए, 2023 के चुनाव का मतलब परिपूर्णता का एहसास है।

प्रश्नः- आपको लगता है कि विपक्षी दल भाजपा के ख़िलाफ़ साथ सकते हैं?

उत्तरः- मुझे लगता है कि यह अंततः होगा माहौल ऐसा बन जाएगा।

प्रश्नः- जब आप चुनाव में जाएंगे तो मध्य प्रदेश के लिए विजन क्या होगा?

उत्तरः-सबसे बड़ी दिक्क़त बेरोज़गारी है। जो भी उद्योग आता है, आर्थिक गतिविधियों को ठिकाने लगा देता है निवेश आकर्षित करना प्राथमिकता होगी। दूसरे खेती बीज और खाद की कमी से ख़राब हो रही है। दरअसल कमी नहीं है बल्कि डिलिवरी मैकेनिज़्म में गड़बड़ी है। ❑❑

भारत जोड़ो का दर्शन वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे

नए भारत जोड़ों का क्या चक्कर चलाया है, आंदोलनजीवी जीवी? किस भारत को जोड़ोगे आप? देख नहीं रहे, राष्ट्र तो अपने आप एकजुट हो रहा है। आपको देश जोड़ने की क्या पड़ी है?''

जब से मैंने 'भारत जोड़ो यात्रा' से जुड़ने की सार्वजनिक घोषणा की है तब से ऐसे कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए आने वाले ये प्रश्न अक्सर तल्ख होते हैं, चुटीले भी। इस यात्रा की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है, लेकिन अब देश के जन आंदोलनों के एक बड़े हिस्से और देश के अग्रणी बुद्धिजीवियों और गणमान्य व्यक्तियों ने भी इसका स्वागत और समर्थन किया है।

उधर कई जन आंदोलनों ने और जन संगठनों ने इस यात्रा का समर्थन करते हुए इसके समानांतर 'नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो' अभियान की घोषणा भी की है। यह संयोग नहीं है कि वैचारिक रूप से अलग अलग दिशा से आने वाली इन आवाज़ों में 'भारत जोड़ो' की अपील की जा रही है। लेकिन हर कोई इसका अलग अलग अर्थ निकाल रहा है।

'हिन्दू-मुस्लिम एकता की यत्रा कर रहे हो न आप? इसकी बहुत ज़रूरत है' यह संदेश एक बुजुर्ग गांधीवादी था। 'जी नहीं, वह है तो, लेकिन वह मुख्य बात नहीं है।' मैंने कुछ झिझकते हुए जवाब दिया। बेशक आज हिंदू मुस्लिम एकता को मज़बूत करना मां भारतीय की पुकार है। भारत विभाजन की त्रासदी के बाद से शायद पहले कभी हिन्दू और मुस्लिम समुदाय के बीच घृणा और वैमनस्य फैलाने की इतनी बड़ी सुनियोजित और सत्तापोषित कोशिश कभी नहीं हुई थी। बेशक देश के दो सबसे बड़े समुदायों को एक-दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काना देशद्रोह है और उन्हें जोड़ना देशभक्ति का पहला धर्म है।

लेकिन आज पहली चुनौती हिन्दू और मुसलमान को जोड़ने की नहीं है। सबसे पहले चुनौती है हिन्दुओं के हिन्दू धर्म की आत्मा से और मुसलमानों को सच्चे इस्लाम से जोड़ने की। बक़ौल स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म की श्रेष्ठता इसमें नहीं है कि वह अपने मत को दूसरे धर्मों से ऊपर मानता है, बल्कि इसमें कि वह दुनिया के सभी धर्मों के सच को स्वीकार करता है। कुरआन शरीफ का संदेश काफिर के सर को तन से जुदा करना नहीं, बल्कि हर इंसान के मन को जोड़ना है। जब तक हर धर्म के अनुयायी अपने-अपने धर्म की संकीर्ण व्याख्या, धार्मिक ठेकेदारों और धर्म के नाम पर नफ़रत के सौदागरों से मुक्त नहीं होते तब तक देश को एक नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत जोड़ो का पहला अर्थ होगा धर्म को उसके मर्म से जोड़ना।

जो बात धर्म पर लागू होती है वह जाति, क्षेत्र, भाषा और भूषा के विभेद के बारे में भी सच है। भारत जोड़ो का मतलब होगा क्षेत्र और भाषा की खाई को पाटना। लेकिन इसके लिए अपनी क्षेत्रीय पहचान को भूलने और अपनी भाषा संस्कृति को छोड़ने का आग्रह करना घातक होगा। ख़ासतौर पर जब उत्तर भारत के हिंदी भाषी बाकी देश वालों को क्षेत्रीयता छोड़ने और भाषाई संकीर्णता से ऊपर उठने का उपदेश देते हैं तो यह वर्चस्ववाद दिखाई देता है।

भारत जोड़ो के लिए हिंदी भाषियों को सबसे पहले यह भाव छोड़ना होगा कि वे देश के मालिक हैं और बाकी सब किराएदार हैं। इस लिहाज़ से यह एक खूबसूरत संयोग है कि यह यात्रा कन्याकुमारी से हिंदी की तुलना में कहीं ज़्यादा पुरानी और समृद्ध तमिल भाषा और संस्कृति को नमन करते हुए की जा रही है।

भारत जोड़ो का मतलब होगा क्षेत्र और भाषा की खाई को पाटना। लेकिन इसके लिए अपनी क्षेत्रीय पहचान को भूलने और अपनी भाषा संस्कृति को छोड़ने का आग्रह करना घातक होगा। ख़ासतौर पर जब उत्तर भारत के हिंदी भाषी बाकी देश वालों को क्षेत्रीयता छोड़ने और भाषाई संकीर्णता से ऊपर उठने का उपदेश देते हैं तो यह वर्चस्ववाद दिखाई देता है।

इसी तरह जाति भेद की खाई को जोड़ने का मतलब यह नहीं होगा कि हम जाति की ओर आंख मूंद लें, या सिर्फ अपने नाम के आगे जातिसूचक शब्द लगाना बंद कर दें। हमारे देश में अपनी जाति न जानने का विशेषाधिकार अगड़ी जातियों के शहरी लोगों को ही होता है। जाति की खाई को पाटने का तरीक़ा यही हो सकता है कि आज भी हमारे समाज में जाति के आधार पर वर्जना, वंचना और विशेषाधिकार के तमाम अवशेषों को समाप्त किया जाए, यानि जाति व्यवस्था की ऊंच-नीच को नष्ट किया जाए। भारत जोड़ो का मतलब होगा जाति तोड़ो।

भारत जोड़ो सिर्फ एक सांस्कृतिक पहचान का आंदोलन नहीं हो सकता। जब तक देश के अन्तिम व्यक्ति के जीवन को खुशहाली से नहीं जोड़ा जाता तब तक भारत जोड़ो केवल एक नारा बनकर रह जाएगा। भारत जोड़ो को साकार करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक कड़वी सच्चाई का सामना करें। पिछले 2 वर्ष में देश में 97 प्रतिशत लोगों की आय घटी है, लेकिन इसी अवधि में मुकेश अंबानी की संपत्ति 3 गुना बढ़ी और अडाणी का साम्राज्य 14 गुना बढ़ा है।

हाल ही में पता लगा कि देश के धनाढ्य वर्ग ने भारत छोड़ो आंदोलन चला रखा है। पिछले कुछ सालों में लाखों भारतीयों ने देश की नागरिकता छोड़ी है। सभी अमीर भारतीय आजकल देश के बाहर निवेश कर रहे हैं। इस सरकार की 'हम दो हमारे दो' वाली आर्थिक नीतियों से यह देश दोफाड़ हो रहा है। उसको चुनौती दिए बिना भारत जोड़ो का सपना देखना भी व्यर्थ है।

भारत जोड़ो का संकल्प देश की राजनीतिक व्यवस्था को अछूता नहीं छोड़ सकता। इस यात्रा की सफलता राजनीतिक दलों और जन आंदोलनों को जोड़ने पर निर्भर करती है। लेकिन इसे हमारे गणराज्य में कुछ बुनियादी जुड़ाव भी करना होगा। आज़ादी के बाद से हमारा लोकतंत्र हमेशा झुका रहा है, लोक पर तंत्र हमेशा हावी रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में लोक बिल्कुल ग़ायब होता जा रहा है, या यूँ कहें कि बस एक भीड़ में बदलता जा रहा है। संविधान प्रदत्त मूल अधिकार सिर्फ कागज़ का टुकड़ा बनकर रह गए हैं।

सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों की जगह जेल में है। राजनीतिक विरोधियों के पीछे पुलिस प्रशासन के साथ-साथ अब सी.बी.आई., ईडी और इंकम टैक्स विभाग भी पड़े हैं। आम आदमी को तो छोड़ दीजिए अब मुख्यमंत्रियों की भी कोई हैसियत नहीं बची है। किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी, बचेगी, बिगड़ेगी इसका फैसला दिल्ली दरबार में होता हैं मूल अधिकारों की हिफाज़त के लिए अब कोर्ट कचहरी के दरवाज़े भी लगभग बंद हो चुके है। ऐसे में भारत जोड़ो का मतलब होगा लोक को तंत्र से जोड़ना और गण को राज्य से जोड़ना।

आज भारत जोड़ो यात्रा का एक ही संकल्प जो सकता है 'वह खंड-खंड में बांटेंगे, हम इन्द्रधनुष को बांधेंगे'। इस अभियान का एक ही नारा हो सकता है 'वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे' भारत को सुंदर भविष्य से जोड़ना ही भारत जोड़ो की सार्थक परिणीति हो सकती है। ❑❑

रोज़गार .....

'स्टोरकीपिंग' के फील्ड में रोज़गार के अवसर

केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, रक्षा सेनाओं अर्द्धसैनिक बलों, अस्पतालों आदि के अंतर्गत भंडारण विभाग में सहायक कर्मचारी के तौर पर स्टोरकीपर का पद होता है।

यह पद संबंधित विभाग की रिक्ति के अनुसार तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के रूप में निर्धारित होता है।

स्टोरकीपर का कार्य

स्टोरकीपर का कार्य होता है कि वह भंडारण विभाग में स्टोर के रख-रखाव से जुड़े कार्यों का निष्पादन वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करे। स्टोर में सामग्रियों की मौजूदगी सुनिश्चित करना, कमी की स्थिति में मांग जारी करना, स्टोर की देखभाल आदि के संबंध के सभी प्रकार के कार्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित गाइडलाइंस के अनुसार करना इत्यादि भी उसके कार्यों में शामिल है। इस प्रकार स्टोरकीपर को स्टोर विभागीय क्रियान्वयन स्तर का सहायक कर्मचारी माना जाता है।

योग्यता तथा चयन प्रक्रिया

स्टोरकीपर की भूमिका भंडारण विभाग में आवश्यक सामग्रियों से जुड़े कार्यों के संचालन के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण होती है इसलिए स्टोरकीपर बनने के लिए आवश्यक कौशल में ज़रूरी है कि आपको स्टोर में सामग्रियों के रख रखाव से जुड़े कार्यों एवं दायित्वों की पूरी जानकारी हो, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों पर कार्यों को तय सीमा में निपटान में पारंगत होना चाहिए और संबंधित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को चलाने में सक्षम होना चाहिए।

स्टोरकीपर बनने के लिए ज़रूरी है कि उम्मीदवार की किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्टोर एवं क्रय में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए, जबकि स्टोर अफसर के पद के लिए उम्मीदवारों को किसी भी विषय में स्नातक और सामग्री प्रबंधन या क्रय एवं भंडार से संबंधित किसी अन्य विषय में एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। स्टोरकीपर बनने के लिए निम्नलिखित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाती है। स्टोर रख-रखाव से जुड़े कार्यों का अनुभव। स्टोर/भंडारण से संबंधित कम्प्यूटरों सॉफ्टवेयर पर कार्य करने में निपुणता।

आयु सीमा

स्टोरकीपर बनने के लिए ज़रूरी है कि उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से 25 वर्ष के बीच हो। हालांकि कुछ संस्थानों में अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष या अधिक भी हो सकती है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में सरकार के नियमानुसार छूट दी जाती है।

चयन प्रक्रिया

स्टोरकीपर के पद पर उम्मीदवारों का चयन आमतौर पर शैक्षणिक रिकॉर्ड, लिखित परीक्षा और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है। हालांकि रिक्तियों के अनुरूप यदि कम संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो संबंधित संस्थान उम्मीदवारों की शॉटलिस्टिंग शैक्षणिक रिकॉर्ड और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर कर सकता है।

स्टोरकीपर का वेतनमान 7वें वेतन आयोग के अनुरूप अच्छा वेतन दिया जाता है।

सरकारी नौकरी के अवसर

स्टोरकीपर के पद केन्द्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, रक्षा सेनाओं, अर्द्धसैनिक बलों, अस्पतालों आदि में होने के कारण इस पद के लिए रिक्तियां समय समय पर इन्हीं संस्थानाओं में निकलती रहती हैं।

सभी रिक्तियों के बारे में भारत सरकार के प्रकाशन विभाग के प्रकाशित होने वाले रोज़गार समाचार, दैनिक समाचार पत्रों एवं सरकारी नौकरी की जानकारी देने वाली वेब साइट्स या एप्स के माध्यम से अपडेट रहा जा सकता है। ❑❑

इस्लामी दुनिया

शेख़ हसीना की भारत यात्रा

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना ने दोनों देशों के बीच समग्र संबंधों को और अधिक विस्तार देने हेतू चार दिवसीय भारत यात्रा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ व्यापक बातचीत हुई जिसके बाद दोनों पक्ष, रक्षा, व्यापार और नदी जल बंटवारे के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों की रूपरेखा पेश कर सकते हैं। नई दिल्ली पहुंचने पर हवाई अड्डे पर केन्द्रीय रेलवे और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की अगवानी की। यह यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मज़बूत करेगी।

काबुल में रूसी दूतावास के बाहर आत्मघाती हमला

काबुल : काबुल में रूसी दूतावास के बाहर पिछले दिनों एक आत्मघाती हमले में दूतावास के दो कर्मचारियों सहित 8 से 10 लोगों के मारे जाने की आशंका है। हालांकि रूसी दूतावास ने इसका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया। रूसी विदेश मंत्रालय के हवाले से सरकारी समाचार एजेंसी आरआईए नोवोस्ती ने कहा कि इस हमले में उसके दो कर्मचारियों की मौत हो गई। मरने वालों में एक हमलावर भी है।

चीन में 6.5 करोड़ लोगों पर यात्रा प्रतिबंध

चीन ने अपने साढ़े छह करोड़ नागरिकों को सख़्त कोविड-19 प्रतिबंधों के तहत लॉकडाउन में रखा है और आगामी राष्ट्रीय अवकाश के दौरान घरेलू यात्रा पर प्रतिबंध की तैयारी कर रहा है। दक्षिण पश्चिम चेंगदू शहर की लगभग 2.1 करोड़ आबादी फ्लैट या रिहाइशी परिसर में क़ैद है, जबकि पूर्वी बंदरगाह शहर तियानजिन में कोविड-19 के 14 मामले सामने आने के बाद अब ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। चीन में हाल में कोरोना वायरस के 1552 नए मामले सामने आए। वायरस को काबू करने के लिए चीन शुरू से ही कड़े क़दम उठाए हैं।

पाक के हार के बाद निशाने पर अर्शदीप

युवा क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने दुबई में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे रोमांचक मैच में एक कैच क्या छोड़ा तुरंत ही ट्रोलर्स के निशानेप र आ गए। लोग सोशल मीडिया पर कैच छूटने की क्लिपिंग शेयर कर कहने लगे कि पाकिस्तान से हार की वजह यही रही। इसके बाद हद तो जब हुई जब अर्शदीप के विकिपीडिया पेज को किसी ने एडिट कर दिया और उनका संबंध ख़ालिस्तान से जोड़कर दिखाया गया। हालांकि उनके बचाव में कई भारतीय क्रिकेटर आ हैं, पर भारत में प्रचलन चल पड़ा है जिससे खिलाड़ियों का मनोबल टूटने की कगार पर है।

कमज़ोर रुपए से बढ़ती मुश्किलें

जयंतीलाल भंडारी

डॉलर की तुलना में रुपया ऐतिहासिक रूप से कमज़ोर है। बीती 17 अगस्त को एक डॉलर की कीमत 79.50 के स्तर पर पहुंच गई थी। चिंताजनक तो यह कि रुपए में अभी गिरावट की आशंका है। रूस/यूक्रेन युद्ध के बाद अब चीन ताइवान तनाव और वैश्विक आर्थिक मंदी के ख़तरे के बीच रुपए की कीमत में बड़ी गिरावट के कारण जहां भारतीय अर्थव्यवस्था की मुश्किलें बढ़ रहीं हैं, वहीं आर्थिक विकास की योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। इतना ही नहीं, असहनीय महंगाई से जूझ रहे आम आदमी की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है।

डॉलर के मुक़ाबले रुपए के कमज़ोर होने का प्रमुख कारण बाजार में डॉलर की मांग बहुत ज़्यादा हो जाना है। वर्ष 2022 की शुरुआत से ही विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआइ) भारतीय बाज़ारों से पैसा निकालने में लगे हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिका के केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज़ दरों में ख़ासा इज़ाफ़ा कर दिया है। दुनिया के कई विकसित देशों के केन्द्रीय बैंक भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी सत्ताई साल बाद चार अगस्त को सबसे अधिक ब्याज़ दर बढ़ाई है। ऐसे में भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने के इच्छुक निवेशक अमेरिका सहित अन्य विकसित देशों में अपने निवेश को ज़्यादा लाभप्रद और सुरक्षित मान रहे हैं और इसलिए भारत से पैसा निकालकर अमेरिका व दूसरे विकसित देशों में निवेश कर रहे हैं।

ग़ौरतलब है कि अभी भी दुनिया में डॉलर सबसे मज़बूत मुद्रा है। दुनिया का करीब 85 प्रतिशत कारोबार डॉलर में होता है। दुनिया के उनतालीस प्रतिशत कर्ज़ डॉलर में दिए जाते हैं। इसके अलावा कुल डॉलर का करीब पैंसद प्रतिशत उपयोग अमेरिका के बाहर होता है। चूंकि भारत अपनी कच्चे तेल की करीब पचासी प्रतिशत ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, इसलिए डॉलर की अहमियत भारत के लिए भी काफी ज़्यादा है। रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनज़र कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी की वजह से भारत को डॉलर ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। साथ ही देश में कोयला, उर्वरक, वनस्पति तेल, दवा निर्माण के कच्चे माल, रसायन आदि का आयात लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में डॉलर की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है। स्थिति यह है कि भारत जितनी निर्यात करता है, उससे अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आयात करता है। इससे देश का व्यापार संतुलन लगातार प्रभावित हो रहा है। एसबीआइ की इको रैप रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022-23 के अप्रैल से जुलाई के चार महीनों में भारत का व्यापार घाटा सौ अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।

सरकार ने खुद यह स्वीकार किया है कि दिसंबर 2014 से अब तक देश की मुद्रा में 25 प्रतिशत तक गिरावट आ चुकी है। इस वर्ष पिछले सात महीनों में ही रुपया करीब सात प्रतिशत तक लुढ़क चुका है। फिर भी अन्य कई विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपए बेहतर स्थिति में है। ब्रिटिश पाउंड, जापनी येन और यूरो जैसी विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपए की स्थिति मज़बूत है। इसका कारण निर्यात, विकास दर वृद्धि की संभावनाएं, पर्याप्त खाद्यान्न भंडार जैसे कारण भी रहे हैं।

रुपया कमज़ोर होने का एक असर देश में बढ़ती महंगाई के रूप में सामने आया है। हाल में प्रकाशित महंगाई के आंकड़ों के मुताबिक जून 2022 में थोक महंगाई दर 15.18 प्रतिशत और खुदरा महंगाई दर 7.01 प्रतिशत के चिंताजनक स्तर पर पाई गई। पांच अगस्त को ब्याज़ दरें और बढ़ाने के मौद्रिक नीति समिति के फैसले का ऐलान करते हुए आरबीआइ के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा भी था कि देश में अभी भी महंगाई की दर ऊंची बनी हुई है। बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण के लिए ही एक बार फिर से रेपो रेट में पचास आधार अंकों की बढ़ोत्तरी की गई है। महंगाई को अभी और नियंत्रित करने के मद्देनज़र रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की सितंबर में होने वाली बैठक में रेपो दर में 35-40 आधार अंकों की और बढ़ोत्तरी की जा सकती है।

इस समय देश में खुदरा महंगाई दर को सात प्रतिशत से घटा कर छह प्रतिशत पर लाने के लिए कई और कारगर प्रयासों की ज़रूरत है। अभी रेपो रेट में कुछ और वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में नगदी प्रवाह को कम किया जाना उपयुक्त होगा। लेकिन लेवल ब्याज दर पर अधिक निर्भरता हानिप्रद हो सकती है। अधिक रेपो रेट बढ़ाने में उपभोक्ता और कारपोरेट दोनों प्रभावित होंगे, मांग घटेगी और इसका अर्थ व्यवस्था भी प्रतिकूल असर करेगा। ऐसे में सबसे ज़रूरी यह है कि देश में निर्यात बढ़ाए जाए और आयात नियंत्रित किए जाएं। निसंदेह कमज़ोर होते रुपए की स्थिति से सरकार और रिजर्व बैंक दोनों चिंतित हैं और इस चिंता को दूर करने के लिए यथोचित क़दम भी उठा रहे हैं। आरबीआइ ने कहा है कि अब वह रुपए की विनिमय दर में तेज़ उतार चढ़ाव की अनुमति नहीं देगा। उसका कहना है कि विदेशी मद्रा भंडार का उपयुक्त उपयोग रुपए की गिरावट को थामने में किया जाएगा। 29 जुलाई को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार करीब पांच सौ तिहत्तर अरब डॉलर रह गया है। अब आरबीआइ ने विदेशी मुद्रा का प्रवाह देश की ओर बढ़ाने और रुपए में गिरावट को थामने, सरकारी बांड में विदेशी निवेश के मानदंड को उदार बनाने और कंपनियों के लिए विदेशी उधार सीमा में वृद्धि सहित कई उपायों की घोषणा की है। ऐसे उपायों से एफआइआइ पर अनुकूल असर पड़ा है और उनकी कुछ कुछ वापसी भी देखी जा रही है।

यकीनन इस समय रुपए की कीमत में गिरावट को रोकने के लिए और अधिक उपायों की ज़रूरत है। इस समय डॉलर के खर्च में कमी और डॉलर की आवक बढ़ाने के रणनीतिक उपाय ज़रूरी है। अब रुपए में वैश्विक कारोबार बढ़ाने के अवसर तलाशने होंगे। पिछले दिनों रिजर्व बैंक ने भारत और अन्य देशों के बीच व्यापारिक सौदों का निपटान रुपए में किए जाने संबंधी महत्वपूर्ण क़दम भी उठाया है। इससे भारतीय निर्यातकों और आयातकों को अब व्यापार के लिए डॉलर की अनिवार्यता नहीं रहेगी। साथ ही अब दुनिया का कोई भी देश भारत से सीधे बिना अमेरिकी डॉलर से व्यापार कर सकता है। इसका एक फायदा यह भी होगा कि डॉलर संकट का सामना कर रहे रूस, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ईरान, एशिया और अफ्रीका सहित कई छोटे छोटे देशों के साथ भारत का विदेशी व्यापार तेज़ी से बढ़ेगा, भारतीय रुपया भी मज़बूत होगा, भारत का व्यापार घाटा कम होगा और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा।

यकीनन इस समय रुपए की कीमत में गिरावट को रोकने के लिए और अधिक उपायों की ज़रूरत है। इस समय डॉलर के खर्च में कमी और डॉलर की आवक बढ़ाने के रणनीतिक उपाय ज़रूरी है। अब रुपए में वैश्विक कारोबार बढ़ाने के अवसर तलाशने होंगे। पिछले दिनों रिजर्व बैंक ने भारत और अन्य देशों के बीच व्यापारिक सौदों का निपटान रुपए में किए जाने संबंधी महत्वपूर्ण क़दम भी उठाया है। इससे भारतीय निर्यातकों और आयातकों को अब व्यापार के लिए डॉलर की अनिवार्यता नहीं रहेगी। साथ ही अब दुनिया का कोई भी देश भारत से सीधे बिना अमेरिकी डॉलर से व्यापार कर सकता है। इसका एक फायदा यह भी होगा कि डॉलर संकट का सामना कर रहे रूस, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ईरान, एशिया और अफ्रीका सहित कई छोटे छोटे देशों के साथ भारत का विदेशी व्यापार तेज़ी से बढ़ेगा, भारतीय रुपया भी मज़बूत होगा, भारत का व्यापार घाटा कम होगा और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा।

जिस तरह चीन और रूस जैसे देशों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमरिकी डॉलर के वर्चस्व को तोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, उसी तरह अब आरबीआइ के निर्णय से भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता के कारण रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिल सकती है। इस समय जब दुनिया रूस और अमेरिकी-यूरोपीय खेमों में बंटती हुई दिखाई दे रही है, तब भारत को अपनी वैश्विक स्वीकार्यता के मद्देनज़र दोनों ही खेमों के विभिन्न देशों में विदेश व्यापार बढ़ाने की संभावनाएं तलाशनी चाहिए। व्यापार में प्रवासी भारतीयों की भूमिका भी बढ़ानी होगी। उत्पाद और सेवा निर्यात बढ़ने से भी विदेशी मुद्रा की आवक बढ़ेगी और देश की आर्थिक मुश्किलें कम होंगी। ❑❑

बंजर होती ज़मीन के ख़तरे

अखिलेश आर्येंदु

खेती-किसानी में रासायनिक खाद का इस्तेमाल कब शुरू हुआ, इसका इतिहास शायद ही कोई जानता हो। माना जाता है कि इससे पहले सन 1840 के आसपास जर्मन वैज्ञानिक लिबिक ने खेती में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के उपयोग की बात दुनिया के सामने रखी थी। बाद में दुनिया के तमाम कृषि वैज्ञानिकों ने उनके शोध को स्वीकारा। लिबिक ने कहा था कि अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश (एनपीके) की खाद बना कर खेतों में डाली जाए तो इससे फसले तेजी से बढ़ सकती हैं। इस नए प्रयोग को दुनिया भर के किसानों ने अपनाया। लेकिन, इसके लगातार इस्तेमाल ने मिट्टी की उर्वरता तो घटा ही दी, बल्कि करोड़ों हेक्टेयर ज़मीन को भी बंजर बना डाला।

दुनियारभर में रेगिस्तानी क्षेत्र तेजी से फैल रहे हैं। मिट्टी की उर्वरता भी कम होती जा रही है। ऐसे में निर्जन रेगिस्तान में जीवन कैसे वापस लाया जाए, यह एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। मृदा वैज्ञानिकों के मुताबिक मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट के चार बड़े कारण हैं। इनमें तेज़ी से होता औद्योगिकीकरण, कृषि में पानी का अत्याधिक इस्तेमाल मवेशियों के लिए चरागाहों का ज़रूरत से ज़्यादा दोहन और सूखे की बढ़ती मियाद। आंकड़े बताते हैं कि रासायनिक खाद के बढ़ते इस्तेमाल से उर्वर और हरे-भरे भूमि क्षेत्र भी बंजर इलाक़ों में तब्दील होकर दुनियाभर में करीब एक अरब लोगों की ज़िन्दगी के लिए ख़तरा बन चुके हैं। इसकी वजह से लाखों जैविक और वनस्पति प्रजातियों का जीवन भी ख़तरे में पड़ गया है। पेड़ पौधों की कई प्रजातियों का तो हमेशा के लिए ख़ात्मा हो चुका है। करोड़ों लोग जो खेती बाग़वानी के जरिए ज़िदगी बसर कर रहे थे, उन्हें पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। आंकलन बताते हैं कि इस सदी के मध्य तक धरती की एक चौथाई मिट्टी मरुस्थलीकरण से प्रभावित होगी। यह एक चिंताजनक पहलू है, लेकिन हालात और बिगड़ने के पहले ही स्थिति को संभालने के लिए यदि आगे नहीं आया गया तो इस विकट संकट से बचा जा सकता है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारी मात्रा में बचे गोला बारुद की रासायनिक सामग्रियों को एनपीके खाद और कीटनाशक बना कर बेचने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने दुनियाभर में नया कारोबार खड़ा कर लिया था। इस कारोबार में कपंनियों को भारी मुनाफा होने लगा था और बाजार में इनकी जड़ें भी मज़बूत हो चली थीं। ज़्यादातर किसान इन कंपनियों द्वारा बनाई खादों पर इस क़दर निर्भर होते चले गए कि इन खादों के बिना कोई फसल उगाते ही नहीं।

भारत और एशियाई देशों में औद्योगिक क्रांति के बाद हरित क्रांति की शुरुआत हुई। खाद और कीटनाशकों का कारोबार करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यह प्रचारित करना शुरू कर दिया था कि बेहतर उपज लेने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल जरूरी है। इसके बाद देश के छोटे बड़े किसान कीटनाशकों का इस्तेमाल इस क़दर करने लगे कि ज़मीन की उर्वरता पर इसका बुरा असर पड़ने लगा। आज हालत यह है कि देश के लाखों किसानों की ज़मीन की उर्वरता इतनी कम हो गई है कि बिना बड़ी मात्रा में रासायनिक खादों और कीटनाशकों के कोई भी फसल होती ही नहीं। कृषि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग कई तरह की समस्याएं पैदा करता है। ज़मीन में जो ज़हरीलापन बढ़ता जा रहा है, वह कई बीमारियों का कारण बन रहा है। इससे मिट्टी में पाए जाने वाली तत्वों का संतुलन भी बिगड़ गया है। इससे किसान नई-नई समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। अब केन्द्र सरकार ने नीम के लेप वाली यूरिया को रासायनिक खाद का विकल्प बताया है लेकिन इस संबंध में यह जानना ज़रूरी है कि इसके इस्तेमाल से मिट्टी और जीव जंतुओं पर कितना निर्माण होता है। दूसरे तत्वों की भी अपनी ख़ास भूमिका है। कैल्शियम पौधे के तने को मज़बूत करता है, तो मैगनिशियम क्लोरोफिल बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधों को मिट्टी में समाए हुए पानी से मिलता है। इन प्राकृतिक तत्वों के आधार पर ही तय होता है कि मिट्टी कैसी है। ज़्यादा अम्लता और ज़्यादा क्षारीयता, दोनों ही पौधों के लिए नुकसानदायक होते हैं।

कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर वर्ष भूमि क्षरण की वजह से पच्चीस लाख टन नाइट्रोजन, तेंतीस लाख टन फास्फोरस और पच्चीस लाख टन पोटाश की क्षति होती है। यदि इस क्षरण को बचा लिया जाए तो हर साल करीब साठ हज़ार लाख टन मिट्टी की ऊपरी परत बचेगी और इससे हर साल करीब पचपन लाख टन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा बचाई जा सकेगी। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार किसानों की आय दोगुना करने और उन्हें खुशहाल किसान बनाने की बात तो करती है, लेकिन प्रश्न यह है कि ज़मीन की घटती उर्वरता को बचाए बग़ैर क्या यह संभव हो सकता है?

केंद्र सरकार की पहल पर मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन सन 1953 में हुआ था तब से लाखों हेक्टेयर भूमि को उर्वर बनाया जा चुका है, लेकिन अभी भी इससे ज़्यादा भूमि ऐसी है जिसे उपजाऊ बनाने की आवश्यकता है। औद्योगिकीकरण, वनीकरण और विकास की दूसरी परियोजनाओं की वजह से ज़मीन का रक़बा भी घटता जा रहा है, साथ ही भूमि का क्षरण भी तेज़ी से हो रहा है। केन्द्र सरकार ने मृदा क्षरण रोकने के लिए गांव-गांव में जागरुकता अभियान चलाए हैं। इसके लिए मृदा संरक्षण के दूसरे अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन किसान भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए पहल नहीं करेगा तो ये सारे अभियान सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि जिन कारणों से ज़मीन बंजर हो रही है, उन कारणों पर ग़ौर किया जाए और ज़मीन की उर्वरता बढ़ाई जाए।

भारत में मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों में कमी गत चार दशकों से ज़्यादा पाई गई। शुरुआत में केवल नाइट्रोजन की कमी थी, लेकिन कटाव, जलभराव, बहुत अधिक कीटनाशकों व रासायनिक खादों का प्रयोग और एक फसल चक्र में ज़रूरत से ज़्यादा फसलों को उगाने जैसे तमाम कारणों की वजह से मिट्टी की उर्वरती घटती गई। आज हालत यह हो गई है कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों के इस्तेमाल के बावजूद अच्छी पैदावार नहीं हो पा रही है। ऐसे में जागरुक किसानों ने मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने वाली जैविक या प्राकृतिक खेती की ओर रुख़ किया है। इसमें न तो कीटनाशकों का प्रयोग होता है और न ही रासायनिक खादों का कंपोस्ट, हरी और जैविक खाद का प्रयोग कर देश के तमाम किसान मिट्टी की सेहत सुधारने में लगे हैं। लेकिन जहां प्राकृतिक खेती नहीं हो रही है, वहां मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने व संरक्षण का कार्य करना बड़ी चुनौती है।

मिट्टी को लेकर हुए तमाम शोधों से यह सामने आया है कि इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन थोड़ी मात्रा में रहना चाहिए। लेकिन न्यून मात्रा में इसमें लोहा, गंधक, सिलिका, क्लोरीन, मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डनेम, तांबा, बोरान और सेलेनियम की मौजूदगी भी ज़रूरी है। ग़ौरतलब है कि कुदरत अपने हिसाब से इन तत्वों की भागीदारी तय करती है, पर इंसान की गतिविधियों की वजह से इन सारे तत्वों का संतुलन गड़बड़ा गया है। दिलचस्प बात है कि मिट्टी में नाइट्रोजन कार्बनिक रूप में भी रहती है और अकार्बनिक रूप में भी। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से अमोनियम के साथ जीवाणु क्रिया करते हैं और अंततः जीवाणुओं से एंजाइम का बुरा असर पड़ रहा है।

केंद्र सरकार की पहल पर मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन सन 1953 में हुआ था तब से लाखों हेक्टेयर भूमि को उर्वर बनाया जा चुका है, लेकिन अभी भी इससे ज़्यादा भूमि ऐसी है जिसे उपजाऊ बनाने की आवश्यकता है। औद्योगिकीकरण, वनीकरण और विकास की दूसरी परियोजनाओं की वजह से ज़मीन का रक़बा भी घटता जा रहा है, साथ ही भूमि का क्षरण भी तेज़ी से हो रहा है। केन्द्र सरकार ने मृदा क्षरण रोकने के लिए गांव-गांव में जागरुकता अभियान चलाए हैं। इसके लिए मृदा संरक्षण के दूसरे अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन किसान भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए पहल नहीं करेगा तो ये सारे अभियान सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि जिन कारणों से ज़मीन बंजर हो रही है, उन कारणों पर ग़ौर किया जाए और ज़मीन की उर्वरता बढ़ाई जाए।

ख़ास ख़बरें

चीन में भूकंप से 30 से अधिक मौतों की ख़बर

चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत की लुडिंग काउंटी में पिछले दिनों 6.8 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, जिसमें 30 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। यह प्रांत पहले से ही कोविड-19 के बढ़ते मामलों और अभूतपूर्व सूखे की समस्या से जूझ रहा है। चीन की सरकारी एजेंसी 'शिन्हुआ' ने चीन भूकंप नेटवर्क केन्द्र के हवाले से बताया कि भूकंप स्थानीय समयानुसार दोपहर 12 बजकर 25 मिनट पर आया और इसका केन्द्र 29.59 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 102.08 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, जमीन से 16 किमी नीचे स्थित था

जिम्बाब्वे में खसरे से 700 बच्चों की जान गई

हरारे : जिम्बाब्वे में खसरे के प्रकोप से जान गंवाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ कर लगभग 700 हो गई है। यह जानकारी देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। कुछ लोग ऐसे देश में टीकाकरण को अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं जहां 1.5 करोड़ की आबादी पर आधुनिक चिकित्सा विरोधी धार्मिक संप्रदायों का प्रभाव है। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें से 37 मौतें एक सितंबर को एक ही दिन में हुई थी।

कनाडा में चाकूबाज़ी में 10 लोगों की मौत, 15 घायल

कनाडा के सस्कै चेवान प्रांत में एक स्थानीय समुदाय और पास के एक अन्य शहर में चाकूबाज़ी की घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। कनाडा पुलिस ने कहा कि 'जेम्स स्मिथ क्री नेशन' और सास्काटून के उत्तर पूर्व में वेल्डन गांव में कई स्थानों पर चाकू घोंपने की घटनाएं हुईं। हालांकि अधिकारी ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि हमले क्यों किए गए।

ट्रस ब्रिटेन की नई पीएम

ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी नेतृत्व के लिए मुक़ाबले में हराया और अब वह प्रधानमंत्री के तौर पर बोरिस जॉनसन का स्थान लिया है। सुनक करीब 21 हजार मतों से पिछड़ गए। 47 वर्षीय ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। इसके साथ ही, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में शीर्ष पद संभालने के लिए सुनक का ऐतिहासिक अभियान ख़त्म हो गया। चुनाव में 82.6 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें सुनक को 60,399 मत जबकि ट्रस को 81,326 मत मिले। ऋषि सुनक ने कहा यह सही है कि अब हम नई प्रधानमंत्री लिए ट्रस के पीछे एकजुट हैं, जो देश को कठिन समय में आगे बढ़ाएंगी।

मदारिसे इस्लामिया इस्लामी तालीम की बेहतरीन व्यवस्था

मदारिस इस्लामिया के क़याम का सिलसिला अहद नबूवत से जारी है, कुरआन व हदीस की तालीम हासिल करने के लिए सबसे पहले जिस जगह का इंतखाब किया गया था वह मस्जिद नबवी में वाकेअ एक मक़ाम है जिसे सफा कहा जाता है, सबसे ज़्यादा अहादीस बयान करने वाले अज़ीम सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ि० इसी सफा के फैज़याफ्ता हैं तमाम दीनी मदारिस और कुरआन व हदीस की तालीम देने वाले इदारों की कड़ियां यहीं से जुड़ती हैं अलग-अलग ज़माने में इन इदारों की शक्लें विभिन्न रही हैं कभी लोगों ने एक जगह का इंतखाब करके वहां तालीम व तआलम का सिलसिला शुरू किया, कभी मस्जिद में दर्स का हलका लगाया गया, कभी किसी आलिम दीन के घर पर जाकर तशनगान उलूम ने अपनी तशनगी बुझाई कभी सरकार ने अपने प्रबंध वाले मदारिस क़ायम किए, कभी नवाबों और मालदारों ने दीनी तालीम के फरोग़ के लिए मदरसा क़ायम किया और सारे इख़्राजात की अदायगी खुद की। 1857 के बाद संयुक्त हिन्दोस्तान को ऐसे हालात से दोचार होना पड़ा कि मदरसों की यह तमाम शक्लें ख़त्म हो गयीं दीनी तालीम की प्राप्ती और कुरआन व हदीस सीखने के लिए इन तमाम रास्तों का इख़्तयार करना बहुत मुश्किल हो गया। मुसलमानों की सत्ता का चिराग़ गुल हो गया मालदारों और नवाबों की ओर से मदारिस की स्थापना का रास्ता भी बन्द हो गया दूसरी ओर देश पर काबिज़ अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को उनके धर्म से दूर रखने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी, शआर इस्लाम से मुसलमानों को दूर करने की हर संभव कोशिश की, ऐसे मुकिश्ल तरीन हालात में हज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी और इनके साथियों ने कुरान व हदीस की तालीम जारी रखने के लिए एक नया रास्ता चुना। सरकार से कोई संबंध नहीं बनाए और किसी तरह का सहयोग लिए बग़ैर मदारिस के क़याम का सिलसिला शुरू किया, आम मुसलमानों के पैसे से आम मुसलमानों के बच्चों को कुरान हदीस की तालीम से आरास्ता करने की तहरीक चलायी, चन्दे पर आधारित एक नए निज़ाम का आगाज़ किया। उसूल हश्तगाना मुरत्तब करके यह हिदायत जारी कर दी कि कुरआन व हदीस की तालीम से हमकिनार करने की गरज़ से क़ायम मदरसों में न तो सरकार से कोई सहयोग लिया जाएगा न ही किसी शख़्स वाहिद (अकेले) के तआव्वुन के सहारे इरादा चलाया जाएगा और न ही नवाब और अमीर पर इन्हसार किया जाएगा बल्कि मिल्लते इस्लामिया के एक एक आदमी से एक-एक पैसा वसूल करके मिल्लत के बच्चों को मिल्ली दीनी और मज़हबी तालीम से आरास्ता किया जाएगा इसलिए किसी आलमे दीन और हाफिज़ कुरान से यह सवाल किया जाता है कि तुम्हें तालीम किसने दी है तो उसका जवाब होता है कि हमें मिल्लत ने तालीम सिखाई है मिल्लत के हम ऋणी हैं हमारी ज़िम्मेदारियां मिल्लत के लिए काम करने की हैं।

इस तहरीक की पहली कड़ी दारुल उलूम देवबंद है चन्दे के निज़ाम पर आधारित वह पहला मदरसा है जिसके बाद यह सिलसिला शुरू होता है और महाद्वीप हिन्द व पाक में तमाम मुसलमानों ने धार्मिक शिक्षा के फरोग़ और शआयर इस्लाम की हिफाज़त के लिए इसी तर्ज़ पर मदरसे क़ायम करना शुरू कर दिया, किसी तफरीक के

कुछ लोगों को चन्दे से बेपनाह नफ़रत है, मदरसों के तालीमयाफ्ता को वह हिकारत की निगाहों से सिर्फ इसलिए देखते हैं कि वह ज़कात और सदक़ा की रक़म खा कर आते हैं। वर्तमान दिनों में अब एक नई तहरीक मदारिस को ज़कात व सदक़ा की रक़म न देने के ख़िलाफ़ छेड़ दी गयी है। एन.जी. ओज. और ट्रस्ट वाले मदरसों के ख़िलाफ़ बयानबाज़ी करके खुद को ज़कात व सदक़ा की रक़म का मुस्तहिक़ बता रहे हैं।

बग़ैर तमाम मसलकों से तआल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम और दर्दमंदाने मिल्लत ने इस तहरीक पर अमल करते हुए चन्दा करके मदरसे की बुनियाद डाली, इस्लामी तालीम के फरोग़ की उन्होंने फिक्र की, उन्होंने कदीम तालीमी निसाब को पेश नज़र रखते हुए एक निसाब तालीम मुरत्तब किया। कुरआन व हदीस और फिक्हा की तालीम को मरकज़ी मौज़ू क़रार दिया, तमामतर तवज्जोह इन्हीं उलूम की प्राप्ती पर केन्द्रित की गयीं, हज़रत शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी को सभी ने अपना इमाम तस्लीम किया। उलमा कराम ने अपने निसाब को आधुनिक शिक्षा से अलहदा इसलिए भी रखा कि हुकूमत की तरफ से आधुनिक शिक्षा सीखने का निज़ाम था, जगह जगह स्कूल व कॉलेजों को स्थापित किया जा रहा था जहां इस्लामी तालीमात के अलावा सारे कोर्सेज़ और विषयों को पढ़ाया जाता था, इसलिए मदरसों के उद्देश्यों में उलूम दीनिया को तरजीह दी गयी और इसी की मरकज़ी मौज़ू क़रार दिया गया, रफ्ता-रफ्ता मदरसों ने भी खुद को ज़माने से मिलाने की कोशिश की और ज़रूरत के अनुसार वहां भी असरी उलूम सिखाने का सिलसिला शुरू हुआ, परिणामस्वरूप कुछ मदरसे तरक्क़ी करते हुए पूरी तरह मॉर्डन बन गए वहां का शिक्षा का पाठयक्रम बिल्कुल ही बदल दिया गया। छुट्टियाँ और शिक्षा का समय भी यूनिवर्सिटी की तरह कर दिए गए, गरज़ व गाइयत भी बदल दी गयी, वहां के फुज़्ला के बारे में यह इम्तियाज़ करना मुश्किल हो गया कि यह मदरसे के पढ़े लिखे हैं या किसी दूसरे इदारे के, कुछ मदरसों ने मामूली बदलाव किया, कुछ ने किसी तरह की तब्दीली के बग़ैर क़दीम निज़ाम को बरक़रार रखा और हर तरह के दबाव के बावजूद यह साफ ऐलान किया कि मार्डन शिक्षा की प्राप्ती के लिए सरकार की ओर से इदारे स्थापित किए गए हैं। धार्मिक शिक्षा का कोई नज़्म नहीं है इसलिए हम अपने निसाब तालीम से कोई समझौता नहीं करेंगे, कुरआन व हदीस का दर्स पूर्व की तरह जारी रहेगा, हाँ यहां से फरागत के बाद विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा सीखने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं।

यह दीनी मदरसे पिछले 15-20 वर्षों से लगातार सरकार और प्रशासन के निशाने पर हैं अनेक बार इन पर आतंकवाद की ट्रेनिंग देने के आरोप लगाए गए हैं सरकार ने इन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में लेने की कोशिश की है, मुसलमानों का एक वर्ग भी मदरसों के मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ है वह दीनी मदरसों में वही सब चाहते हैं जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में लागू हैं बहुत से बुद्धिजीवी मदरसों के निज़ाम तालीम को दकियानूसियत से ताबीर करते हैं, हाल ही में बी.बी.सी. के एक पत्रकार ने यहां तक लिख दिया कि दारुल उलूम देवबंद और दारुल उलूम नदवातुल उलूम में सरकार का हस्तक्षेप ज़रूरी हो गया है क्योंकि यहां का निसाब तालीम अत्याधिक पुराना है जिसे पढ़ने के बाद विद्यार्थियों को कट्टरवादिता की तरग़ीब मिलती है और फरागत के बाद वह मिल्ली, रफाही और समाजी काम करने के बजाए आतंकवाद की राह इख़्तयार करते हैं इसलिए देश को कट्टरपंथी और हिंसा की राह पर जाने से रोकने के लिए इन इदारों में सरकार हिन्द का हस्तक्षेप ज़रूरी हो गया है, मुझे नहीं मालूम कि बीसीसी का क्या मक़सद था लेकिन इतना बताना ज़रूरी है कि भारत के तमाम मदरसों का शिक्षा पाठयक्रम कुरान हदीस और फिक्हा इस्लामी पर आधारित है शिक्षा का उद्देश्य मज़हबी उलूम से रूशनास कराना है, अब अगर इन इदारों पर कट्टरपंथी को फरोग़ देने का इल्ज़ाम आयद किया जाता है तो इसका मतलब कुरान व हदीस और इस्लामी उलूम कट्टरपंथी पर आधारित है? कुछ लोगों को चन्दे से बेपनाह नफ़रत है, मदरसों के तालीमयाफ्ता को वह हिकारत की निगाहों से सिर्फ इसलिए देखते हैं कि वह ज़कात और सदक़ा की रक़म खा कर आते हैं। वर्तमान दिनों में अब एक नई तहरीक मदारिस को ज़कात व सदक़ा की रक़म न देने के ख़िलाफ़ छेड़ दी गयी है। एन.जी.ओज. और ट्रस्ट वाले मदरसों के ख़िलाफ़ बयानबाज़ी करके खुद को ज़कात व सदक़ा की रक़म का मुस्तहिक़ बता रहे हैं। इन तमाम मसायल के साथ भारत जैसे देश में सबसे बड़ा अलमिया यह है कि मौलवी तबक़े को शक की निगाहों से देखा जाता है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और इस तरह के दूसरे तमाम स्थलों पर मौलवी बिरादरी की चेकिंग आम लोगों से कुछ अलग अंदाज़ में की जाती है। बात-बात पर उन्हें आतंकवादी, कट्टरपंथी कह दिया जाता है। इनकी तमामतर हरकात व सकनात पर ख़ास नज़र रखी जाती है दूसरी ओर आम मुसलमान इन्हें मासूम अन अल खता समझते हैं। मामूली गलती पर भी यह कहा जाता है कि फलां ने मौलाना होने के बावजूद इस अम्र का इरतकाब कर लिया, गोया शरिअत पर अमल सिर्फ मौलवी बिरादरी की ज़िम्मेदारी है और इनके हर काम पर एतराज़ किया जाता है, खुलासा यह कि मुआशरा

बाक़ी पेज 11 पर

नूरे क़ुरआन

(सूरा अल बक़रह नं० 02)

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

और जब हमने तुमसे वचन लिया था और तूर पर्वत को तुम्हारे ऊपर खड़ा किया था (और आदेश था कि) जो हमने तुमको दिया है उसको दृढ़ता से पकड़ो और सुनो, उन लोगों ने कहा कि हमने सुन लिया और हमने नहीं माना और उनके दिलों में उनके इनकार के कारण उसी बछड़े की मुहब्बत रचा बसा दी गयी।

अर्थात् तौरेत के आदेशों के मानने की जो ज़िम्मेदारी दी गयी उस पर दृढ़ता से जमे रहो। उस समय क्योंकि पहाड़ सर पर था, जान के भय से केवल ज़बान से ''हमने सुन लिया'' कह दिया। अर्थात् तौरेत के आदेश हमने सुन लिये और तत्पश्चात् दिल से कहा ''कि हमने नहीं माना'' अर्थात् हमने तौरत के आदेश स्वीकार नहीं किए। वास्तव में उनके इस कपट का कारण यह था कि बछड़े की पूजा उनके दिल में उनके इंकार के कारण जम चुकी थी। इनकार का वह ज़ंग उनके हृदयों से बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ बल्कि धीरे-धीरे बढ़ता ही गया।

आप कह दीजिए कि तुम्हारा ईमान तुम को बुरी बातें सिखाता है। यदि तुम ईमान वाले हो, आप कह दीजिए कि यदि आख़िरत का घर अल्लाह के यहां और लोगों को छोड़कर केवल तुम्हारे लिए है तो तुम मरने की तमन्ना (इच्छा) करो यदि तुम सच कहते हो।

यहूदी कहते थे कि जन्नत में हमारे अतिरिक्त कोई न जायेगा और हमको अज़ाब न होगा। अल्लाह ने कहा कि निश्चित जन्नती हो तो मरने से क्यों डरते हो?

रुकू नं० 11

और उन पापों के कारण जो उन्होंने अपने हाथों समेटे हैं कदापि मैत की कभी तमन्ना (इच्छा) नहीं करेंगे और अल्लाह गुनाहगारों को भली-भांति जानता है और आप उनको सब लोगों से अधिक जीवन पर लालच करने वाला पायेंगे और अल्लाह का साझी बनाने वालों से भी अधिक लालची। उनमें से एक-एक व्यक्ति चाहता है कि हज़ार वर्ष की आयु पाये और इतना लम्बा जीना उसको अज़ाब से बचाने वाला नहीं है और अल्लाह देखता है जो वे करते हैं।

अर्थात् यहूदियों ने ऐसे बुरे काम किये हैं कि मृत्यु के नाम से डरते फिरते हैं और समझते हैं कि मरते ही मुसीबत में फंस जायेंगे यहां तक कि मुश्रिकों से भी अधिक जीने का लालच रखते हैं इससे उनके दावे का खण्डन हो गया।

आप कह दीजिए कि जो व्यक्ति जिब्रील से शत्रुता रखता है, जिब्रील ने तो यह कुरआन अल्लाह के आदेश से आपके हृदय में उतारा है। (उस कुरआन की हालत यह है) कि सच्चा बताने वाला है उस किताब को जो उससे पहले है और ईमान वालों को सीधा मार्ग दिखाता है और शुभ सूचना सुनाता है, जो कोई अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके रसूलों का और जिब्रील का और मीकाईल का दुश्मन हो तो अल्लाह उन इनकारियों का दुश्मन है।

यहूदी कहते थे कि जिब्राईल फरिश्ता इस रसूल के पास वह्यी लाता है वह हमारा शत्रु है हमारे पूर्वजों को उससे बहुत कष्ट पहुंचा है। यदि जिब्राईल के स्थान पर दूसरा फरिश्ता वह्यी लाए तो हम हज़रत मुहम्मद सल्ल० पर ईमान ले आयें। इस पर अल्लाह ने कहा। ''फरिश्ते जो कुछ भी करते हैं, अल्लाह ही की ओर सकते हैं'' अपनी ओर से कुछ भी नहीं करते जो उनका दुश्मन है अल्लाह वास्तव में उनका दुश्मन है।

न्यायमूर्ति ललित

बार से सीधे देश की शीर्ष अदालत तक

न्यायमूर्ति यूयू ललित के वकालत के शुरुआती दिनों की बात करें तो पढ़ाई पूरी करने के बाद जून 1983 में वह महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल में पंजीकृत हुए और उन्होंने एडवोकेट एम.ए. राणे के साथ वकालत शुरू की। वर्ष 1985 में वह दिल्ली चले आए और सीनियर एडवोकेट प्रवीन के. पारेश के साथ जुड़ गए। वर्ष 1986 से 1992 के बीच उन्होंने भारत के पूर्व अटार्नी जनरल सोली सोराबजी के साथ काम किया। तीन मई 1992 को उन्होंने उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट ऑन रिकार्ड के रूप में पंजीकरण हासिल किया और 29 अप्रैल 2004 को उन्हें उच्चतम न्यायालय के सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया गया।

न्यायमूर्ति उदय रमेश रलित भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति ललित आज़ाद भारत के इतिहास में महज़ दूसरे प्रधान न्यायाधीश हैं, जो सीधे बार से सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचे। उनसे पहले न्यायमूर्ति एस. एम. सीकरी जनवरी 1971 में जब देश के 13वें प्रधान न्यायाधीश बने थे तो वह वकालत से सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुकत होने वाले पहले न्यायाधीश थे। गर्वनमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई से कानून की पढ़ाई करने वाले न्यायमूर्ति यूयू ललित का परिवार पिछली एक सदी से क़ानून और न्यायपालिका से जुड़ा है। उनका जन्म महाराष्ट्र के शोलापुर में यू.आर. ललित के यहां नौ नवंबर 1957 को हुआ। उनके पिता मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के अतिरिक्त न्यायाधीश रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकील के तौर पर वकालत भी करते रहे हैं। उनके दादा रंगनाथ ललित भी वकालत के पेशे से जुड़े थे।

न्यायमूर्ति यूयू ललित के वकालत के शुरुआती दिनों की बात करें तो पढ़ाई पूरी करने के बाद जून 1983 में वह महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल में पंजीकृत हुए और उन्होंने एडवोकेट एम.ए. राणे के साथ वकालत शुरू की। वर्ष 1985 में वह दिल्ली चले आए और सीनियर एडवोकेट प्रवीन के. पारेश के साथ जुड़ गए। वर्ष 1986 से 1992 के बीच उन्होंने भारत के पूर्व अटार्नी जनरल सोली सोराबजी के साथ काम किया। तीन मई 1992 को उन्होंने उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट ऑन रिकार्ड के रूप में पंजीकरण हासिल किया और 29 अप्रैल 2004 को उन्हें उच्चतम न्यायालय के सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया गया।

वर्ष 2011 में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली की पीठ ने उन्हें 2-जी स्प्रेक्ट्रम मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) का विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति के समय कहा गया था कि उनकी पेशेवर समझ, कानूनी सवालों को धैर्य के साथ स्पष्ट करने का गुण और मामले को बड़े सरल अंदाज़ में, लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ पेश करने का उनका हुनर उन्हें इस पद के लिए योग्य बनाता है।

जुलाई 2014 में उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम ने न्यायमूर्ति यूयू ललित को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत करने की सिफारिश की और उन्हें 13 अगस्त 2013 को न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वकालत से सीधे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद तक पहुंचने वाले वह मात्र छठे वकील हैं। न्यायालय के तौर पर उन्होंने ऐसे फैसले सुनाए जो उनकी क़ानूनी बारीकियों की समझ के साथ ही सामाजिक दायित्वों के निर्वाह की मिसाल बन गए।

दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र में होगी चार चरण की सख़्ती

प्रदूषण के ख़िलाफ़ लड़ाई इस बार और सख़्त होगी। इसके लिए दिल्ली एनसीआर के वायु गुणवत्ता आयोग ने चरणबद्ध कार्य योजना (ग्रेडिड एक्शन प्लान) में संशोधन किया है और चार चरण में विभाजित कर दिय है। यह रिपोर्ट हाल ही में वायु गुणवत्ता आयोग ने केन्द्र सरकार को सौंपी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आयोग ने पुराने प्रावधानों में बदलाव करके इस वर्ष के लिए सख़्ती को और बढ़ा दिया है।

इस बार दिल्ली और एनसीआर के राज्यों में वायु गुणवत्ता के पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर ही सख़्ती लगनी शुरू हो जाएगी। यह पूर्वानुमान प्रतिदिन होने वाले गुणवत्ता स्तर के बदलाव के आधार पर तैयार होगा। आयोग ने वायु गुणवत्ता की पहली श्रेणी में 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बेहद खराब, 401 से 450 की श्रेणी गंभीर और इससे अधिक की श्रेणी को अधिक गंभीर श्रेणी में रखा है।

प्रदूषण स्तर बढ़ते ही तत्काल कार्रवाई की जा सके, इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय एक उपसमिति भी बनाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया है कि जैसे ही प्रदूषण की स्थिति तीसरी श्रेणी में पहुंचती है तो राज्य स्तर पर मुख्य सचिव हालात की सीधी निगरानी करेंगे। इस बार सीधे तौर पर आम जनता को जोड़ने के लिए हर श्रेणी का सिटीजन चार्टर भी वायु गुणवत्ता आयोग ने तैयार किया है। चरणबद्ध कार्य योजना को 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू किया गया था। इसमें पहली बार व्यापक स्तर पर बदलाव किया है।

पहला चरण : धूल कण कम करने के लिए क़दम उठाने होंगे और निर्माण व तोड़फोड़ की गतिविधियां रुक जाएगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकाय यह भी सुनिश्चित करेंगे के खुले में कहीं पर कचरा नहीं डाला जाएगा। धूल कण कम करने के लिए पानी छिड़काव की मशीनें प्रयोग होंगी और मशीन से सफाई होगी। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा।

दूसरा चरण: हर दिन केवल मशीनों से सफाई सुनिश्चित करनी होगी। पानी का छिड़काव करना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य होगा। होटल, रेस्तरां समेत अन्य जगहों पर कोयले का इस्तेमाल बंद होगा और आपात सेवाओं को छोड़कर अन्य के लिए डीजल का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। पार्किंग के दाम बढ़ाकर निजी वाहनों के उपयोग को कम किया जाएगा।

तीसरा चरण : सड़क से वाहन कम करने के लिए आम जनता के लिए ख़ास जगहों से सार्वजनिक बस सेवा की पहल ज़रूरी होगी। सरकारी परियोजनाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर निर्माण गिराने का काम रोका जाएगा। ईट के भट्ठे पत्थर तोड़ने वाली मशीनें और खुदाई पर भी पूरे एनसीआर में रोक होगी।

चौथा चरण : ज़रूरी सामान लेकर अन्य राज्यों में राष्ट्रीय राजधानी आने वाले ट्रक के अतिरिक्त अन्य ट्रक दिल्ली एनसीआर में प्रवेश नहीं करेंगे। इसी पर अनिवार्य सेवाओं के अतिरिक्त उपयोग किए जा रहे डीजल वाहन इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जहां पर प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की सुविधा नहीं है, वहां सभी औद्योगिक गतिविधियां बंद हो जाएंगी। राज्य सरकार इस स्थिति में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दे सकती है और केन्द्र सरकार के कर्मचारी घर से ही अपना काम करेंगे।

केरल के टीएमसी मेडिकल कॉलेज में नेहरू थे पहले मरीज़

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु ने 1951 में केरल के सबसे पुराने अस्पताल तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज (टीएमसी) का उद्घाटन किया था। उस वक़्त तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस बीच उनकी कए उंगली इमारत में लगी एक धातु की ग्रिल में गलती से फंसने के कारण चोटिल हो गई थी। ऐसे में इस अस्पताल में पंडित जवाहर लाल नेहरु यहां इलाज कराने वाले पहले मरीज़ थे।

दस्तावेज़ों के अनुसार, नेहरू ने ही क्रमशः 1951 और 1954 में टीएमसी और एमसीएच दोनों का उद्घाटन किया था। एक पुरानी किताब के मुताबिक, फरवरी 1954 में राजकीय चिकित्सा कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन करने वाले नेहरू की उंगली इमारत में लगी एक धातु की ग्रिल में गलती से फंसने के कारण चोटिल हो गई थी, जिसके बाद प्रख्यात सर्जन स्वर्गीय डॉ. आर. केसवन नायर के मार्ग दर्शन में उनका तत्काल इलाज किया गया। नायर मेडिकल कॉलेज के संस्थापक अधीक्षक भी थे। मलयालम भाषा में लिखी किताब के अनुसार, 'राजकीय चिकित्सा कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे नेहरू की उंगली धातु की एक ग्रिल में फंसने के कारण चोटिल हो गई थी। इस तरह नेहरू, अस्पताल में इलाज करवाने वाले पहले मरीज, जबकि डॉ. केशवन नायर अस्पताल में किसी मरीज़ का इलाज करने वाले पहले डॉक्टर बने।' तीन वर्ष बाद इसी परिसर में टीएमसी के प्रतिष्ठित राजकीय चिकित्सा कॉलेज अस्पताल (एमसीएच) की स्थापना की गई। टीएमसी और एमसीएफ ने सिर्फ अपनी तरह के पहले चिकित्सकीय प्रतिष्ठान थे, बल्कि इनका ऐतिहासिक महत्व इस तथ्य को लेकर भी है कि सात दाशक पहले वहां इलाज कराने वाले पहले मरीज़ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। डॉ. केशवनर नायरः वैद्यसहस्राथिले इतिहामम' (द लिजेंड ऑफ मेडिकल साइंस) शीर्षक से छपी किताब दिवंगत चिकित्सक के संस्मरणों का संग्रह है। किताब में वयोवृद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और चिकित्सा इतिहासकार डॉ. के. राजशेखरन नायर के हवाले से कहा गया है कि उद्घाटन के पहले दिन नेहरू की एक झलक पाने के लिए उल्लूर में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। डॉ. केशवन के शिष्यों में से एक राजशेखरन के ज़ेहन में आज भी उस ऐतिहासिक दिन की यादें ताज़ा हैं।

विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी का लंबे समय से शतक नहीं बनाना अजीब : कपिल

अपनी कप्तानी में भारत को 1983 में पहली बार विश्वकप का ख़िताब दिलाने वाले पूर्व भारतीय ऑलराउंडर कपिल देव का कहना है कि विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी का करीब तीन वर्ष से शतक नहीं बनाना अजीब बात है। कपिल ने साथ ही कहा कि कोहली में प्रतिभा और जुनून की कोई कमी नहीं है। उन्हें फार्म हासिल करने के लिए बस एक अच्छी पारी की ज़रूरत है। 16 सितंबर से शुरू हो रही लीजेंडस् लीग क्रिकेट सहित अन्य मुद्दों पर कपिल देव जी से हुई ख़ास बातचीत के प्रमुख अंश

सवाल:- एलएलसी में पुराने दिग्गज एक बार फिर खेलते हुए नज़र आएंगे? ऐसा टूर्नामेंट पहले आया होता तो आप भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कुछ क्रिकेट खेल पाते?

जवाब:- हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लेने वाले क्रिकेटर एक बार फिर खेल रहे हैं। सौरव गांगुली और वीरेन्द्र सहवाग जैसे दिग्गज खिलाड़ी आए हैं। मैं जितना भी खेला उससे खुश हूं। आज जो क्रिकेट खेल रहे हैं वे जब क्रिकेट छोड़ेंगे तो उनके लिए ऐसी लीग होना कोई बुरी बात नहीं है। टेनिस, गोल्फ सहित अन्य खेलों में भी ऐसा होता है। कई बार क्रिकेटरों के मन में संन्यास लेने के बाद मलाल रह जाता है कि शायद थोड़ा और खेल लेते, तो उनको भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैदान पर उतरता देख खुशी हो सकती है।

सवाल:- आपको तो क्रिकेट के बाद गोल्फ का प्यार मिल गया था? आपने क्रिकेट के बाद गोल्फ भी बहुत अच्छा खेला.?

जवाब:- मुझे प्यार ज़िन्दगी से मिला है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोशिश बरकरार रहती है। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं बाकी खेलों को भी खेल सकता हूं, उसकी ज़्यादा खुशी होती है।

सवाल:- एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत के शीर्ष तीन बल्लेबाज़ टी-20 के हिसाब से खेल पा रहे हैं?

जवाब:- हर बार सभी खिलाड़ी तो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। टी-20 विश्व

बाक़ी पेज 11 पर

झूलन का क्रिकेट के प्रति जुनून बेजोड़ : हरमनप्रीत

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्रिकेट में झूलन गोस्वामी के योगदान को याद करते हुए कहा कि इस अनुभवी तेज गेंदबाज़ का खेल का प्रति जुनून बेजोड़ है और टीम में कोई भी उनकी जगह नहीं भर सकता है। झूलन के नाम पर अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है।

हरमनप्रीत ने टीम के इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना होने की पूर्व संध्या पर मीडिया से बातचीत में कहा, 'वह प्रत्येक मैच में उसी तरह के जुनून के साथ उतरती हैं जो कि बेजोड़ है। कोई उनका मुक़ाबला नहीं कर सकता।' हरमनप्रीत ने विश्व कप 2009 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूलन की कप्तानी में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पर्दापण किया था। उनकी इस दिग्गज भारतीय तेज गेंदबाज़ के साथ कई यादें जुड़ी हैं जिनके नाम पर 201 वनडे में रिकॉर्ड 252 विकेट दर्ज हैं। झूलन इस प्रारूप में 200 से अधिक विकेट लेने वाली एकमात्र गेंदबाज़ हैं।

हरमनप्रीत ने कहा, 'मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता। उन्होंने कहा 'वह एक ऐसी खिलाड़ी हैं जो हमेशा एक ही तरह का प्रयास करती हैं। वह दो-तीन घंटे गेंदबाज़ी करती हैं। वह अब भी उसी तरह की कड़ी मेहनत कती हैं जैसे कि अपने शुरूआती दिनों में किया करती थी। हरमनप्रीत ने कहा, 'आपको शायद ही कोई ऐसी गेंदबाज़ दिखे जो उनकी तरह नेट पर कड़ी मेहनत करता हो। क्रिकेट के प्रति उनमें जिस तरह का जुनून है वह किसी में नहीं है।' उन्होंने कहा, 'एक क्रिकेटर के तौर पर और एक व्यक्ति के रूप में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वह हम सभी के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। देश में कई खिलाड़ियों ने उनको खेलते हुए देखकर यह खेल अपनाया।' झूलन ने इस वर्ष मार्च में न्यूजीलैंड में खेले गए वनडे विश्व कप में हिस्सा लिया था लेकिन वह दक्षिण अफ्रीका के ख़िलाफ़ भारत के अन्तिम ग्रुप मैच से पहले चोटिल हो गई थी।

हर बार यह सोचकर उतरता हूं कि यह मेरा आख़िरी टेस्ट होगा : एंडरसन

40 वर्ष के जेम्स एंडरसन इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं मानो उनकी आयु 20 वर्ष हो, जबकि अब वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल तेज़ गेंदबाज़ हैं। एंडरसन ने कहा, 'मैं कल संन्यास ले सकता हूं और मुझे खुशी होगी।' हालांकि, अपने कप्तान बेन स्टोक्स की खुशी के लिए स्विंग के किंग की संन्यास की कोई योजना नहीं है। छह माह पहले ही एंडरसन को वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद उस सीमर को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्हें कहीं अकेला छोड़ दिया गया है। लेकिन, मैनेजमेंट में बदलाव की वजह से स्टोक्स और कोच मैक्कुलम के नेतृत्व में एंडरसन के कैरियर को नया जीवनदान मिला। एंडरसन आस्ट्रेलिया के दिग्गज ग्लेन मैक्ग्रा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय विकेट (951) लेने वाले तेज़ गेंदबाज़ बन गए। एंडरसन ने कहा, 'हर बार जब मैं खेलता हूं तो मुझे लगता है कि यह आख़िरी बार हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ अनुभव का आनंद ले रहा हूं। मैं खेलना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैं वास्तव में अच्छी गेंदबाज़ी कर रहा हूं मैं बस वही करना चाहता हूं जो मैं कर रहा हूं।'

बदबू बगल की परेशानी बगलगीर की

गर्मी के मौसम में पसीना आना आम बात है। अब गर्मी के साथ उमस बढ़ रही है, इसमें पसीना अधिक निकलता है। सामान्यतया पसीना निकलना स्वस्थ शरीर की पहचान है। मगर घबराहट, बेचैनी या किन्ही अन्य कारणों से पसीना निकलता है, तो वह किसी गंभीर समस्या का कारण भी हो सकता है। मगर पसीना तब खुद एक समस्या बन जाता है, जब उसमें दुर्गंध आती हो। आपके आसपास बैठे लोग दूरी बनाने लगते हैं, नाक भौं सिकोड़कर दिखाते हैं। बहुत सारे लोग पसीने की बदबू मिटाने के लिए खुशबूदार द्रव्य इस्तेमाल करते हैं। पर लंबे समय तक उससे भी दबाना मुश्किल होता है। इसलिए पसीने की बदबू के कारण और उससे बचने के उपाय जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ सामान्य घरेलू नुस्खों से पसीने की बदबू दूर भगाई जा सकती है। भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं, जो पसीने और उसकी दुर्गंध से छुटकारा दिला सकती है।

कारण

पसीने से बदबू तभी आती है, जब पसीना देर तक कपड़े में बना रहे और उसमें बैक्टीरिया चिपके रहते हैं। कई लोग एक ही वस्त्र बिना धोएं कई दिन तक पहनते हैं इस तरह उनमें चिपके बैक्टीरिया बदबू पैदा करते हैं। इसके अलावा कपड़ों की वजह से भी बदबू पैदा होती है। अगर कपड़े पॉलिएस्टर अधिक है, तो पसीना भी अधिक निकलेगा और उसमें बदबू भी ज़्यादा आएगी। सूती कपड़ों में बदबू कम पैदा होती है इसलिए कमीज, जुराबें आदि इस मौसम में सूती ही पहनें, तो बेहतर होगा। इसके लिए हर समय साफ सफाई का ध्यान रखता होता है। जब शरीर में पानी से ज़्यादा कैफीन की मात्रा हो जाती है और आप नियमित स्नान नहीं करते, तो पसीने में बदबू आने लगती है।

घरेलू उपाय

अगर आपके पसीने से बदबू आती है, तो इससे बचने के लिए बगलों में नारियल तेल या ज़ैतून का तेल लगाना फायदेमंद होता है। अगर सूखी त्वचा की समस्या से परेशान है तो रोज़ाना सोने से पहले चेहरे पर नारियल तेल से मालिश करे। इसके अलावा यह शरीर की दुर्गंध को कम करता है। इसमें लोरिक एसिड होता है, जो पसीना पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कम करता है। आप शरीर के उन हिस्सों में नारियल तेल लगाएं, जहां दुर्गंध आती है। पुदीना के पत्ते में कई तरह के औषधीय गुण होते हैं। पुदीने के पत्ते को उबालकर नहाने के पानी में मिलाएं और फिर नहाएं। इससे पसीने की दुर्गंध नहीं आएगी। रोज़ाना पुदीने के पत्ते से स्नान करने से तरोताज़ा भी महसूस करेंगे।

इसके अलावा बेकिंग सोडा भी शरीर की दुर्गंध से छुटकारा दिलाने में काफी मददगार होता है। बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिला कर उन हिस्सों में लगाएं जहां से बदबू आती है। इसके सूखने के बाद स्नान कर लें। इसके अलावा आप चाहे, तो नहाने के पानी में चुटकी भर बेकिंग सोडा डाल कर नहा सकते हैं।

फिटकरी भी इसमें बहुत लाभकारी होता है। फिटकरी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो पसीने को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। नहाने के पानी में फिटकरी मिलाएं और नहा लें। पसीने की दुर्गंध से छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल न करें।

खानपान का ध्यान

इस मौसम में थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें। जब भी घर से बाहर निकलें, पानी की बोतल साथ रखें। पानी अधिक मात्रा में पीने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और निर्जलीकरण यानि डिजाईड्रेशन की समस्या नहीं होती है। इससे रक्तचाप जैसी समस्या को कम करने में भी मदद मिलती है। अगर अधिक पसीने या दुर्गंध की समस्या हो तो आपको चाय और काफी का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैफीन पाया जाता है और इससे डिहाईड्रेशन की परेशानी हो सकती है।

कैल्शियम शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है और पसीने की बदबू भी कम करता है। अगर आपको सुबह कैल्शियम का सेवन करना है, तो अपने आहार में कम वसा वाला दूध शामिल करें। इसके अलावा गर्मियों में दही या छाछ भी कैल्शियम का अच्छा विकल्प हो सकता है।

गर्मियों में कई ऐसे मौसमी फल और सब्जियां मिलती हैं और जिनमें भरपूर मात्रा में पानी पाया जाता है। आप खाने में तैलीय चीजों की जगह इन पानी से भरपूर फलों और सब्ज़ियों का सेवन कर सकते हैं। इससे शरीर की बदबू को कम करने में मदद मिलती है। इसके लिए लौकी, भिंडी, खीरा, संतरा, तरबूज़, स्ट्राबेरी, अनन्नास आदि का सेवन अवश्य करें। ये प्राकृतिक रूप से शरीर की दुर्गंध को कम करते हैं।

ज़ैतून का तेल यानि आलिव ऑयल एंटीआक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो आपके पाचन तंत्र को मज़बूत बनाता है और शरीर के तापमान तथा पसीने के स्तर को नियंत्रित रखता है। इसे आप अपने खाने और सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं।

पसीने से बदबू आने का कारण अधिक वसा वाले खाद्य पदार्थ भी हो सकते हैं। इसके लिए आप भोजन में रेशेदार यानि फाइबर युक्त भोजन, जैसे साबुत अनाज, सफेद ब्रेड, ओट्स और दलिया खा सकते हैं। ❑❑

हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल

क्या धर्म का अधिकार निर्धारित ड्रेस वाले स्कूल में भी हो सकता है लागू?

कर्नाटक के हिजाब प्रतिबंध विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अधिकार निर्धारित यूनिफार्म वाले स्कूल में भी लागू हो सकता है? कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या सेकुलर देश के सरकारी स्कूल में धार्मिक पोशाक पहन सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि आपके पास किसी भी धर्म को मानने का अधिकार हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उस स्कूल में धर्म का पालन कर सकते हैं जहां निर्धारित यूनिफार्म है? क्या कोई विद्यार्थी उस स्कूल में हिजाब पहन सकती है जहां निर्धारित यूनिफॉर्म है। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सालिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि यह मुद्दा काफी सीमित है और यह शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन से संबंधित है। इस पर पीठ ने उनसे सवाल किया कि अगर कोई लड़की हिजाब पहनती है तो स्कूल में अनुशासन का उल्लंघन कैसे होता है? इस पर एएसजी ने कहा, अपनी धार्मिक प्रथा या धार्मिक अधिकार की आड़ में कोई यह नहीं कह सकता कि मैं ऐसा करने का हकदार हूं इसलिए मैं स्कूल के अनुशासन का उल्लंघन करना चाहता हूं। वहीं कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने राज्य सरकार के 5 फरवरी 2022 के उस आदेश का हवाला दिया जिसके जरिये स्कूल कॉलेजों में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसे कुछ मुस्लिम छात्रओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। नवदगी ने कहा कि राज्य ने नहीं बल्कि शैक्षणिक संस्थानों ने यूनिफार्म निर्धारित किए हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकारी आदेश छात्रें के किसी भी अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है।

याचिकाओं का विरोध कर रहे सरकारी वकीलों के यह पूछे जाने पर कि क्या हिजाब पहनना संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत एक अनिवार्य अभ्यास है, पीठ ने कहा कि इस मुद्दे को थोड़ा अलग तरीके से समझा जा सकता ह। यह जरूरी हो भी सकता है और नहीं भी। पीठ ने कहा, हम जो कह रहे हैं वो यह है कि क्या आप किसी सरकारी संस्थान में अपनी धार्मिक रवायत के पालन पर जोर दे सकते हैं। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं।

वहीं मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे जज आते हैं जो तिलक लगाते हैं या पगड़ी पहनते हैं। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि इसे धर्म से न जोड़ें। पगड़ी धर्म से जुड़ी नहीं है और उनके दादाजी अदालत में इसे पहना करते थे। इसके बाद धवन ने कहा कि अदालत के समक्ष मुद्दा उन लाखों महिलाओं से संबंधित है, जो शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड का पालन करती हैं, लेकिन उसके साथ हिजाब भी पहनना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मामले में शीर्ष अदालत का फैसला महत्वपूर्ण होगा। यह अदालत जो फैसला देगी उसे पूरी दुनिया देखेगी। सुनवाम्र के दौरान आई दलीलों पर पीठ ने कहा कि अगर कर्नाटक शिक्षा अधिनियम ड्रेस कोड निर्धारित करने की अनुमति नहीं देता है, तो सवाल यह है कि क्या अधिनियम ड्रेस कोड को प्रतिबंधित कर सकता है। इस तर्क पर कि हिजाब प्रतिबंध से महिलाएं शिक्षा से वंचित रह सकती हैं, पीठ ने कहा कि राज्य यह नहीं कह रहा है कि वह किसी भी अधिकार से इनकार कर रहा है।

शेष.... प्रथम पृष्ठ

ये शर्मिन्दगी वाली बात नहीं है कि आज राजनीति में आपराधिक तत्वों की बढ़ती भागीदारी से, वह अब इसे 'राजनीति अपराधीकरण' नहीं बल्कि ''अपराधी का राजनीतिकरण'' कहा जाए जो अतिश्योक्ति न होगी।

आज सत्ता प्राप्ति के लिए सब कुछ किया जाता है, आज समय की आवश्यकता है कि ऐसा क़ानून बनाया जाए जिस से चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदे और विकास की बात की घोषणा करते हैं, अगर उस कसौटी पर वह खरा नहीं उतरते तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान रखा जाए।

आजकल मुफ्त में दी जाने वाली योजनाओं का विरोध भी हो रहा हे, जो इस कहावत को सही दर्शाता है ''हम मुफ्त दे तो सही, दूसरे दे तो रेवड़ी संस्कृति'' प्रत्येक नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में ही लगे रहते हैं और जनता की भलाई के कामों की ओर ध्यान देने की कोशिश भी नहीं करते और अपनी राजनीति करने में ही व्यस्त रहते है। स्वास्थ्य और शिक्षा जो प्रत्येक आम नागरिक का मौलिक अधिकार है, वह राज्य के अधिकार में हो और बाक़ी और अन्य सुविधाओं के लिए ये होना चाहिए कि मुफ्त में दी जाने वाली योजनाओं को रोज़गार से जोड़ दिया जाए। काम करके जो धन प्राप्त होता है, उस धन की आदमी क़द्र करता है और फ्री के चक्कर में तो कामचोरी की ओर अग्रसर होता है, इसलिए आवश्यकता है कि प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति से उसकी आयु, क्षमता और योग्यता के अनुसार काम लेने की योजनाओं पर काम किया जाए और बदले में उसे उचित और निष्पक्ष वेतनमान दिया जाए। कुछ विद्वानों का यह भी मश्वरा है कि मुफ़्त की योजनाओं के बारे में विशेषज्ञों की राय ली जानी चाहिए और अगर वह इससे सहमत हो तो फिर तो फिर उसमें कोई आशंका नहीं होनी चाहिए, हालांकि ये एक नामुमकिन व्यवस्था ही है। पहली बात तो यह कि करदाताओं से किस-2 योजना पर राय ली जाएगी इसका उद्देश्य तो हज़ारों पांव वाले जानवर की तरह है जिसका कोई उद्देश्य या अंत नहीं है। फिर प्रश्न वही लौट कर आता है कि काम का आदमी फ्री के चक्कर में निकम्मेपन की ओर जा सकता इसे किसी भी तरह परोपकारी या विकासत्मक योजना नहीं कहा जा सकता। जहां तक चुनावी वायदों का प्रश्न है तो उनको भी यकीनी बनाया जाना चाहिए और जिस दल या प्रत्याशी ने जो वायदे चुनावी के दौरान किए है उनको पूरा न करने के पर उसकी जवाबदेही तय करने का सिस्टम बनाया जाना चाहिए। उनके नतीजे पर काम दिखे और आम जनता को फायदा पहुंचे। इस सिलसिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन सही प्रकार से जीने का अधिकार और गणतंत्र के लिए जद्दोजहद साफ नज़र आए। हम जब चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली की बात करते हैं, तो मालूम होता है कि चुनाव आयोग को अपनी ताक़त और अधिकार का सही ज्ञान प्रथम बार टी. एन. शेषन ने कराया था और आम जनता तक ये बात भी पहुंची थी कि भारत में चुनाव आयोग जैसा एक शक्तिशाली आयोग भी है। मिस्टर शेषन ने पहली बार चुनावी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग की शक्तियां दिखाई थीं, चुनावों में होने वाले खर्चों की सीमा बताई थी, निर्दलीय उम्मीदवारों के चयन का नियम, चुनावी विज्ञापन, साधन आदि राजनीतिक नेताओं की हवाई यात्रा, चुनावी सभाओं में सरकार की सीमाएं सोशल मीडिया का प्रयोग, एक देश एक स्कैच वोट, मतदाता पहचान पत्र और आधारकार्ड आदि ऐसे लाभ के कार्य है जिन पर एक अधिक बार चर्चा हो जाती है, लेकिन आज भी इन मुद्दों को अपने अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचने का इंतज़ार है। वर्तमान समय में चुनावों संबंधी सीमितियों का गठन, आयुक्तों के सुझावों पर कार्रवाई की जाए। ❑❑

शेष.... विराट कोहली जैसे....

कप आ रहा है और इनका लय में आना ज़रूरी है। टीम के पास इतना लंबा बल्लेबाज़ी क्रम है। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं लगती, लेकिन फिर भी यही कहूंगा कि शुरू के तीन मुख्य खिलाड़ी अगर फार्म में रहें तो टीम के लिए बेहतर होगा। 150 रन आज के समय में टी-20 में बड़ा नहीं माना जाता। 170-175 रन कह सकते हैं कि एक लड़ने लायक़ स्कोर हो जाता है और इससे ज़्यादा फिर आप उसे बेहतर स्कोर कहना शुरू कर देते हो, जिससे जीत काफी हद तक पक्की हो जाती है। एक समय था 150 रन टी-20 में मैच जीतने के लिए पर्याप्त स्कोर माना जाता था, लेकिन आज के समय खिलाड़ी थोड़ा अपना सतर ऊपर लेकर गए हैं या यह कह सकते है। कि गेंदबाज़ उस जगह पर थोड़ा पड़ गए हैं।

सवाल:- एक ओर इंग्लैंड टैस्ट में भी बेजबॉल क्रिकेट की ओर बढ़ रहा है, दूसरी ओर के.एल. राहुल, रोहित शर्मा और विराट उस स्ट्राइक रेट से रन नहीं बना पा रहे जिसकी ज़रूरत है। क्या हम टी-20 विश्व कप के लिए तैयार हैं..?

जवाब:- टीम तैयार हो रही है। एशिया कप से इन सब टीमों को टी-20 विश्व कप से पहले थोड़ा और इस प्रारूप में खेलने का एक अवसर है। एक अभ्यास करने का मौक़ा मिला है, जो टी-20 विश्व कप से पहले इन टीमों के लिए बेहतर है। फार्म की बात करें तो इस पर हमेशा चर्चा होती रहेगी।

सवाल:- भुवनेश्वर कुमार शानदार स्विंग करा रहे हैं और विकेट ले रहे हैं। आस्ट्रेलिया में वह कितने कारगर साबित हो सकते हैं?

जवाब:- जब तक भुवनेश्वर स्विंग करते रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि तब तक उनको कोई छू सकता है। बहुत ही अच्छे गेंदबाज़ हैं, लेकिन आज भारत के पास इतने बेहतर खिलाड़ी मौजूद हें कि अगर एक क्रिकेटर खराब फार्म या फिटनेस के कारण बाहर भी हो तो चिंता की बात नहीं है। भुवनेश्वर सुलझे हुए क्रिकेटर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सीमाएं पता हैं। उस सीमा में दुनिया में उनसे बेहतर कोई गेंदबाज़ नहीं है।

सवाल:-हमारे पास हादिक पांडया और जडेजा के रूप में दो ऑलराउंडर मौजूद है। जडेजा को चौथे नंबर पर खिलाने के प्रयोग को कैसे देखते हैं?

जवाब:- यह टीम प्रबंधन के ऊपर निर्भर करता है कि क्या करना है। हम लोग तो सिर्फ बाहर से देख रहे हैं। मैच जीतना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ❑❑

शेष.... मदारिसे इस्लामिया....

और समाज में एक मौलवी को मुख़्तलिफ़ अज़ीयतों, मुश्किलों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, इक़बाल मरहूम ने अपनी नज़्म इब्लीस की मजलिम शूरा में इब्लीस की ज़बान से इस हक़ीक़त को इस तरह अदा किया है।

है अगर मुझको ख़तर कोई भी तो
इस उम्मत से है
जिसकी खाकतरी में है अब तक
शरार आरज़ू
खाल-खाल इस क़ौम में अब तक
नज़र आते हैं वह
करते हैं अश्क़ सहरगाही से जो
ज़ालिम वज़ू,

लेकिन इन सबके बावजूद दीनी तालीम हासिल करने वाले विद्यार्थियों की तादाद न सिर्फ दिन- ब-दिन बढ़ती जा रही है, बल्कि अब ग़रीब और मध्य वर्ग के साथ बड़े घरानों का भी रुझान दीनी तालीम की ओर होने लगा है और इनके बच्चे मदरसों में तालीम प्राप्त कर रहे हैं मदरसों की बढ़ती हुई संख्या के बावजूद बहुत से मदरसों का शिकवा है और बहुत से विद्यार्थी दाख़िले से महरूम हो जाते हैं, यह सब इस बात की दलील है कि मदरसे अपने मिशन पर बढ़ रहे हैं, अपने मक़सद में कामयाब हैं और वहां आज भी वही सबक़ पढ़ाए जाते हैं यह सब इस बात की दलील है कि मदरसे अपने मिशन पर बढ़ रहे हैं अपने मक़सद में कामयाब हैं, और वहां आज भी वही सबक़ पढ़ाए जाते हैं जो 14 सौ साल पहले मस्जिद नबवी में असहाब सुफ्हा को पढ़ाए जाते थे।

मदरसों की अफादियत और अहमियत के तआल्लुक से अल्लामा इक़बाल का यह नज़रिया भी देख लीजिए ''जब मैं तुम्हारी तरह जवान था तो मेरे कल्ब की कैफियत भी ऐसी ही थी मैं भी वही कुछ चाहता था, जो तुम चाहते हो, इन्क़लाब, एक ऐसा इन्क्लाब जो हिन्दुस्तान के मुसलमानों की मग़रिब की सम्मानीय और मुतमदिन कौमों के दोश बदौश खड़ा कर दे लेकिन यूरोप को देखने के बाद मेरी राय बदल गयी, इन मक्तबों को इसी हाल में रहने दो, ग़रीब मुसलमानों के बच्चों को उन ही मक्तबों में पढ़ने दो अगर यह मुल्ला और दुरवेश न रहे तो जानते हो क्या होगा? जो कुछ होगा उसे मैं अपनी आंखों से देख आया हूं, अगर हिन्दोस्तान के मुसलमान मक्तबों के असर से महरूम हो गए तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हस्पानिया (स्पेन) में मुसलमानों की आठ सौ वर्षीय हुकूमत के बावजूद आज गरनाता और करतबा के खंडहर और अल हमरा और बाबुल अख्वातीन के सिवा इस्लाम के पैरवां और इस्लामी तहज़ीब के आसार का कोई नक़्श नहीं मिलता, हिन्दोस्तान में भी आगरा के ताजमहल और दिल्ली के लाल क़िला के सिवा मुसलमानों की आठ सौ साला हुकूमत और तहज़ीब का कोई निशान नहीं मिलेगा।

कल एक शौरीदा बारगाहे नबी पे रो-रो के कह रहा था कि मिस्र व हिन्दोस्तान के मुस्लिम बिनाए मिल्लत मिटा रहे हैं,

ग़ज़ब है यह रहबराने खुदबी खुदा
तेरी क़ौम को बचाए
मुसाफिराने रह हरम को रहे
कलीसा दिखा रहे हैं ❑❑

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : **4 Sep. 2022** Posting Days : **MON-TUE.** at **N.D.P.S.O.** New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

मंज़र पस-मंज़र — मीम.सीन.जीम

आज के दौर में बच्चों की बदलती खेल आदतें खतरनाक

अल्पसंख्यक कौन कहां कितनी संख्या में

आज के दौर में बच्चों की बदलती खेल आदतें खतरनाक

हम में से प्रत्येक ने जो आज से लगभग 10-15 वर्ष पहले खेल का दिवाना हुआ करता था, शायद ही कभी सोचा होगा कि आने वाली नस्लें ये खेल ऐसे नहीं खेल पाएगी जैसे हम खेल रहे हैं। आजकल प्रत्येक दिन अखबारों में ये समाचार अवश्य मिल ही जाता है कि फलां बच्चे ने सोशल मीडिया से प्रभावित होकर कुछ न कुछ अच्छा या बुरा काम अंजाम दे दिया। आजकल मोबाईल, इंटरनेट आदि की लत के शिकार बच्चे तक दहला देने वाले अपराध कर बैठते हैं।

आज आर्थिक दबावों के समक्ष अभिभावकों को फुर्सत ही नहीं है जो उसे यह बता सकें कि उसके जीवन में उपयोगी चीजों का चयन करने की दिशा क्या हो। संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों की सीख देने वाले परिवार और स्कूल भी उनके बचपन से दूर छिटक रहे हैं। वर्तमान का कटु सत्य यह भी है कि परिवारों में बुज़ुर्गों की भूमिका ख़त्म सी हो गई है।

इस नई दुनिया ने लड़के और लड़कियों के मनोमस्तिष्क को आक्रामक बना दिया है। इस संदर्भ को प्रमाणित करतीं तमाम घटनाएं देखने-सुनने को मिलती रहती हैं। मोबाईल इस्तेमाल करने और पबजी जैसे हिंसक खेल खेलने से रोकने जैसी बात पर ही बच्चे माता पिता को मार डालने या खुदकुशी जैसा आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। पिछले कुछ समय में ऐसी घटनाएं तेजी से बढ़ी है। कुछ माह पहले लखनऊ में सोलह वर्ष के एक किशोर ने अपनी मां की हत्या कर दी थी। कारण पता चला कि वह उसे मोबाईल पर पबजी खेल खेलने को मना करती थी यह कशोर दसवीं कक्षा का छात्र था। ऐसी घटनाओं को देखते हुए लगता है कि इंटरनेट के माध्यम से उभरती इस हिंसा के समाज शास्त्र को समय रहते समझने और इस समस्या का समाधान खोजने की महती आवश्यकता हैं ऐसी घटनाएं परिवार, समाज और सामाजिक परिवेश पर प्रश्न खड़े करती हैं। इन घटनाओं से लगता है कि बच्चों के समाजीकरण में अपनी खास भूमिका का निभाने वाली परिवार और स्कूल जैसी प्राथमिक संस्थाओं की ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं सिमटती जा रही है। इसका असर यह हुआ है कि बच्चे अपनी दुनिया अलग बनाते जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि पिछले कुछ दशकों से कम्प्यूटर और इंटरनेट सूचनाओं ने एक संवेदनाशून्य समाज गढ़ दिया है। आज सूचनाओं के इस भाव शून्य समाज में लोगों के सामने यम सामाजिक प्रश्न जवाब मांग रहा हे कि आखिर क्यों इस इंटरनेट आधारित समाज में हमारे बीच आपसी संवाद बनाने वाली सस्थाएं दम तोड़ रही हैं? आज इंटरनेट पर उपलब्ध तरह तरह के हिंसक खेलों के सामने हमारे मस्तिष्क को तरोताज रखने वाली सामाजिक और शैक्षिक क्रियाएं समाज से क्यों ग़ायब होती जा रही है?

विद्यालयों में पठन पाठन, शिक्षण और शिक्षक की मौदगी के बाद भी इंटरनेट से जुड़े आभासी खेल हिंसा की हदें क्यों पार करते जा रहे हैं? तकनीकी व डिजिटल समाज के विकास के इस संक्रमणकाल में इन सवालों के जवाब खोजना ज़रूरी हो गया है। कड़वी सच्चाई यह है कि परिवार के बिखराव का बचपन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हैं दादा दादी, नाना-नानी की देख-रेख में पलने वाला बचपन अब कम्प्यूटर, इंटरनेट, टीवी और वीडियो गेम जैसे संचार माध्यमों के बीच पल रहा हे। उसके इस मनो शारीरिक विकास में दैहिक समाज नदारद है। आज आर्थिक दबावों के समक्ष अभिभावकों को फुर्सत ही नहीं है जो उसे यह बता सकें कि उसके जीवन में उपयोगी चीजों का चयन करने की दिशा क्या हो। संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों की सीख देने वाले परिवार और स्कूल भी उनके बचपन से दूर छिटक रहे हैं। वर्तमान का कटु सत्य यह भी है कि परिवारों में बुज़ुर्गों की भूमिका ख़त्म सी हो गई है। छोटे परिवारों के बाद बने कामकाजी एकल परिवारों में मां-बाप भी अब बच्चों के बचपन से ग़ायब हो रहे हैं। ऐसे अकेले वातावरण में बच्चे अपने मनोरंजन की चीजों के चयन के लिए स्वतंत्र हो गए हैं।

एक दौर था जब बच्चे पार्क में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, इत्यादि खेल खेलते दिख जाया करते थे। अब बच्चे इंटरनेट दुनिया के बड़े उपभोक्ता बन चुके हैं। घर-परिवार में बच्चों की सुनवाई ठीक से न होने के कारण आभासी दुनिया उन्हें अपना दोस्त बनाने को आतुर है। यही वजह है कि अबोध बच्चे आभासी दुनिया के चुंगल में फंसते जा रहे हैं। देखने में यह भी आ रहा है कि परिवारों में बच्चों को भौतिकतावादी सुविधाएं देकर मां-बाप अपनी सामाजिक भूमिका की इतिश्री समझ रहे हैं। लिहाज़ा बच्चे घर की चारदीवारी में बंद होकर आभासी दुनिया में चले जाते हैं। इंटरनेट पर हिंसक खेल खेलते हैं। खेल में जीतने के लिए उन्हें कम्प्यूटर, वीडिया अथवा मोबाइल के पर्दे पर किसी चरित्र को मारने में बहुत मज़ा आने लगता है। नतीजा यह होता है कि इन कृत्रिम चरित्रों को मार मार कर पलते और बड़े होते ये बच्चे अपने वास्तविक जीवन में भी ऐसा करने से नहीं चूकते। तथ्य बताते हैं कि आज देश दुनिया में ऑनलाइन गेम का अरबों खरबों का कारोबार है। वर्ष 2019 में ऑनलाइन गेम का वैश्विक कारोबार सैंतीस अरब डॉलर से भी ज़्यादा का रहा था। वर्ष 2025 तक एक सौ बीस अरब डॉलर से भी अधिक ही जाने का अनुमान है। केपीएमजी की रिपोर्ट बताती है कि भारत में भी यह कारोबार अभी बारह हजार करोड़ रुपए से अधिक का है। ऑनलाइन खेल खेलने वालों की संख्या से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि कोरोना काल में इनकी संख्या पैंतीस करोड़ के आसपास थी, जो इस वर्ष के अंत तक पचास करोड़ से भी ज़्यादा हो जाने का अनुमान है। हालांकि भारत सरकार ने पिछले दो सालों में चीन के सौ से ज़्यादा ऐप पर प्रतिबंध तो लगाया है, मगर इसके बावजूद नाम बदल-बदल कर ये हिंसक खेल अपना करतब दिखाने से नहीं चूक रहे हैं।

अल्पसंख्यक कौन कहां कितनी संख्या में

उच्चतम न्यायालय ने हिन्दुओं के लिए अल्पसंख्यक दर्जे की मांग से जुड़े एक मामले में स्पष्ट किया कि देश में धार्मिक और भाषाई समुदायों के माइनॉरिटी स्टेटस का प्रश्न राज्य स्तर पर ही तय होना चाहिए। भारत जैसे बड़े देश में अलग-अलग राज्यों में इन समुदायों की स्थिति और संख्या अलग अलग है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक भाषा बोलने वालों या धार्मिक समुदाय को बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक क़रार देना कुछ मामलों में इंसाफ़ का मज़ाक़ बना सकता है। उदाहरण के लिए, कोई मराठी भाषी व्यक्ति महाराष्ट्र में भाषाई तौर पर बहुसंख्यक समुदाय का सदस्य होता है, लेकिन दिल्ली आने पर वही अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य हो जाता है। धार्मिक समुदायों की भी वही स्थिति है। बौद्ध, सिख वगैरह को तो छोड़िए हिन्दुओं की भी यही स्थिति है कि देश के कई राज्यों में वह नगण्य संख्या में है। उदाहरण के लिए, हिन्दुओं की आबादी मिजोरम में 2.75 प्रतिशत, नगालैंड में 8.74 प्रतिशत और मेघालय में 11.52 प्रतिशत है। केन्द्र शासित क्षेत्रों में देखा जाए तो कई क्षेत्रों में यह संख्या और कम मिलती है। उदाहरण के लिए, लद्दाख में यह संख्या महज़ 01 प्रतिशत, लक्ष्यद्वीप में 2.77 प्रतिशत और कश्मीर में 04 प्रतिशत है। भारत जैसे हिन्दू बहुल देश के अलग अलग हिस्सों में हिन्दुओं की नगण्य उपस्थिति हमारी विविधता का जीता जागता सबूत है। साथ ही यह बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य स्तर पर किए जाने की ज़रूरत भी रेखांकित करती है लेकिन इससे आगे धार्मिक और क़ानूनी जटिलताओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। मसलन, अगर इस प्रश्न को लिया जाए कि किसी समुदाय को बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक दर्जा देने का अधिकार किसके पास है तो केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे ही अन्य मामलों में साफ-साफ कह चुकी है कि यह अधिकार उसके पास है। इसी तरह अगर आबादी के कम या ज़्यादा अनुपात के आधार पर हिन्दुओं को अल्पसंख्यक दर्जे से वंचित किए जाने संबंधी याचिकाकर्ताओं की दलील पर कहा कि जब तक ऐसे ठोस मामले सामने नहीं आते, इन दावों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। ज़ाहिर है, इस मामले में सरलीकरण से काम नहीं चलेगा। बहरहाल, मामला अभी

अगर आबादी के कम या ज़्यादा अनुपात के आधार पर हिन्दुओं को अल्पसंख्यक दर्जे से वंचित किए जाने संबंधी याचिकाकर्ताओं की दलील पर कहा कि जब तक ऐसे ठोस मामले सामने नहीं आते, इन दावों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। ज़ाहिर है, इस मामले में सरलीकरण से काम नहीं चलेगा। बहरहाल, मामला अभी अदालत में चल ही रहा है।

अदालत में चल ही रहा है। इस दौरान इससे जुड़े तमाम जटिल पहलू सामने आएंगे और उन सभी संबद्ध पक्षों की राय भी सामने आएगी। फिलहाल, यह ज़रूर स्पष्ट हो गया है कि माइनॉरिटी स्टेट्स और उससे जुड़े अधिकार संबंधी क़ानूनी मसले 'आम धारणा' के आधार पर नहीं हल किए जा सकते। और, इसमें शक करने की कम से कम अब कोई वजह नहीं है कि आबादी में ख़ास समुदाय के अनुपात तय करने का काम राज्य स्तर पर ही होना चाहिए। ❑❑

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-

❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ Paytm या PhonePe द्वारा 9811198820 पर SHANTI MISSION

❸ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण
SBI A/c 10310541455
Branch: Indraprastha Estate
IFS Code: SBIN0001187

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in —— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक	Rs.130/-
6 महीने के लिए	Rs.70/-
एक प्रति	Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन :- 011-23311455

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक मोहम्मद तैयब ख़ान ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173